



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937

No. 94]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (एनटीसीएफ) के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा

सं. 15/32/2013-डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बनी सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली या पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "नायलान टायर कार्ड फेब्रिक" (जिसे एतदपश्चात एनटीसीएफ या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच दिनांक 29.10.2003 की अधिसूचना सं. 14/20/2003-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2005 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/20/2003-डीजीएडी के तहत की गई सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकार ने संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 27.04.2005 की अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

3. यतः, संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच दिनांक 16 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2009 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी के तहत यह निष्कर्ष निकाला था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने के पाटन एवं परिणामी क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की सिफारिश की थी

और केंद्रीय सरकार ने संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 29 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 41/2009-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया।

4. यतः, एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली (जिसे एतद्पश्चात् याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने अपनी दो अन्य सदस्य कंपनियों अर्थात् मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड के साथ मिलकर अधिनियम और नियमों के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता/पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए दायर किया है और संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरंतरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

5. घरेलू उद्योग की ओर से उपर्युक्त दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(क) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 17 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. 15/32/2013-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के ससत अधिरोपण करने की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए प्रारंभ की कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्रीय सरकार ने दिनांक 16 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 21/2014-सीमाशुल्क के तहत दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तक बढ़ा दी है।

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित इससे पूर्ववर्ती जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने इस जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन का आरोप लगाते हुए आवेदनपत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को इसकी सूचना प्रेषित की।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए एक सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. 15/32/2013-डीजीएडी जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सहित एक पत्र सभी ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को अग्रेषित किया और नियमावली के अनुसार उन्हें अपने विचारों से निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत लिखित रूप में उपलब्ध कराने के लिए एक अवसर प्रदान किया।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई। आवेदनपत्र की एक प्रति, अनुरोध करने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।
- ङ. संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित पत्र की प्रतियां और निर्यातक प्रश्नावली सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित, भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को भी प्रेषित की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वह संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देश के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को सुझाव दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली संबद्ध देश के सभी निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रेषित की :
 - (i) निंग्बो नायलान कंपनी लिमिटेड
 - (ii) जुन्मा टायर कार्ड कंपनी लिमिटेड
 - (iii) क्विंगडाओ लि आन्चुआंग स्टाफ कंपनी लिमिटेड
 - (iv) क्विंगझोऊ हेली कैमिस्ट्री फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - (v) शान्डांग बाओरन (होलिंडग) कंपनी लिमिटेड
 - (vi) यन्ताइ गुओ गुओ हैंडीक्राफ्ट कंपनी
 - (vii) झांग्जिआंगरू रूइक्वि कार्ड फेब्रिक कंपनी लिमिटेड

- (viii) शान्डांग आन्दा सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
- (ix) वीफांग ग्रेट डैगन कैमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड/शान्डांग पालीटेक्स
- (x) जिआंगसु किंफा कैमिकल कंपनी लिमिटेड
- (xi) ताइझोऊ कैमिकल फाइबर्स कंपनी
- (xii) शान्डांग हुआलियान ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- (xiii) झिआंगसु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड
- (xiv) वुजिआंग डिंगझेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
- (xv) शान्डांग हुआलियान ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- (xvi) वीफांग सेन्यु ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- (xvii) फोशान सिटी शुन्डी डिस्ट्रिक्ट किंफा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
- (xviii) जिआंगसुस्टीड
- (xix) शान्डांग हेशेन्ग कैमिकल वीविंग कंपनी लिमिटेड
- (xx) शान्डांग शाउगुआंग रूइहुआ नान-वोवेन फेब्रिक्स कंपनी लिमिटेड
- (xxi) अचिन वेविंग एंड स्ट्रिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
- (xxii) बालिंग पेट्रोकेमिकल्स

छ. निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर और प्रस्तुतिकरण केवल मैसर्स जिआंगसु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड से ही प्राप्त हुए। तथापि, मैसर्स जिआंगसु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली दायर नहीं की। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा जांच और वर्तमान जांच की शुरुआत संबंधी प्रस्तुतिकरण मैसर्स जुन्मा टायर कार्ड कंपनी लिमिटेड, निंगबो नायलान कंपनी लिमिटेड, हुआइआन नायलान कैमिकल फेब्रिक कंपनी लिमिटेड और निंगबो जिन्लुन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि अपने विचारों से निर्धारित समय-सीमा के अंदर लिखित रूप में अवगत कराएं :

- (i) बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
- (ii) अपोलो टायर्स लिमिटेड, गुडगांव
- (iii) फाल्कान टायर्स लिमिटेड, मैसूर
- (iv) बिरला टायर्स, कोलकाता
- (v) गुडयीयर इंडिया लिमिटेड, बल्लभगढ़
- (vi) टीवीएस श्रीचक्रा लिमिटेड मदुरई
- (vii) जे. के. टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली
- (viii) सिएट लिमिटेड, मुंबई
- (ix) एमआरएफ लिमिटेड, मुंबई
- (x) आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए), नई दिल्ली

झ. अपोलो टायर्स ने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया। आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए), अपोलो टायर्स और जे. के. टायर एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए।

ञ. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 थी। तथापि, क्षति विश्लेषण की प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

- ट. घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोत आईबीआईएस, मुंबई से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने तुलना करने के लिए उक्त आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी ने पाया कि आईबीआईएस आंकड़ों में रिपोर्ट की गई आयात की मात्रा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों में रिपोर्ट की गई आयात मात्रा से बहुत अधिक (लगभग 20 प्रतिशत अधिक) थी और इसलिए प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति विश्लेषण के लिए आईबीआईएस आंकड़ों पर भरोसा किया है जैसाकि प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थिति में विभिन्न पिछली जांचों में किया है।
- ठ. उन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रेषित की उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।
- ड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में खुला रखा गया।
- ढ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप यथासंभव सीमा तक की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 21 जनवरी, 2015 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। इस सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों की लिखित प्रस्तुतिकरण/प्रत्युक्तियां भी दायर करें।
- त. जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई है और उनका इस प्रकटन विवरण में समाधान कर दिया गया है।
- थ. घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया है।
- द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया और उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ वहां, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें।
- ध. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच को भारी अवरोध उत्पन्न किया है, वहां प्राधिकारी ने उक्त जांच "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर की है तथा उन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना गया है।
- न. *** इस प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत उसे वैसा ही माना गया है।
- प. जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 56.89/-रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान उत्पाद का दायरा

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

9. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- (i) विचाराधीन उत्पाद "नायलान टायर कार्ड फेब्रिक" या एनटीसीएफ है। एनटीसीएफ नायलान का एक फेब्रिक होता है जिसका प्रयोग मुख्यतया टायर कार्ड के लिए किया जाता है। एनटीसीएफ का अनुप्रयोग विभिन्न के आटोमोटिव टायरों जैसे बस और ट्रक टायर, दुपहिया वाहनों के टायरों, साइकिल टायरों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायरों, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के टायरों में किया जाता है।
- (ii) नायलान टायर कार्ड फेब्रिक का उत्पादन यार्न की विभिन्न डेनियर्स का प्रयोग करके किया जाता है। इस फेब्रिक का प्रयोग टायर को पुनर्वलित करने के लिए किया जाता है। इस उत्पाद की बिक्री "ग्रीन फेब्रिक" और "डिण्ड फेब्रिक" के अंतर्गत भी की जाती है। यह इस विचाराधीन उत्पाद की भिन्न-भिन्न प्ररूप है। भारतीय टायर उद्योग ग्रीन और डिण्ड

दोनों तरह के फेब्रिक की खरीद करता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग एनटीसीएफ के सीटीसी ग्रेड का भी उत्पादन करता है जिसका प्रयोग साइकिलों के टायर विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है।

- (iii) सभी प्रकार के एनटीसीएफ विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आते हैं और उन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 59 के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 5902.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- (iv) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम तथा इसके पश्चात निर्णायक समीक्षा जांच में ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

ग.2. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

10. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (एनटीसीएफ) है। एनटीसीएफ नायलान का एक फेब्रिक होता है जिसका प्रयोग मुख्यतया टायर कार्ड के लिए किया जाता है। एनटीसीएफ का अनुप्रयोग विभिन्न के आटोमोटिव टायरों जैसे बस और ट्रक टायर, दुपहिया वाहनों के टायरों, साइकिल टायरों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायरों, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के टायरों में किया जाता है। नायलान टायर कार्ड फेब्रिक का उत्पादन यार्न की विभिन्न डेनियर्स का प्रयोग करके किया जाता है। इस फेब्रिक का प्रयोग टायर को पुनर्वलित करने के लिए किया जाता है। इस उत्पाद की बिक्री "ग्रीग फेब्रिक" और "डिप्ड फेब्रिक" के अंतर्गत भी की जाती है। यह इस विचाराधीन उत्पाद की भिन्न-भिन्न प्ररूप है। भारतीय टायर उद्योग ग्रीग और डिप्ड दोनों तरह के फेब्रिक की खरीद करता है। विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच तथा पिछली सभी निर्णायक समीक्षा जांच में था।

12. सभी प्रकार का एनटीसीएफ विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आता है और उसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 59 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 5902.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.4. समान वस्तु

13. आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद तथा संबद्ध देश से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आश्रयक अंतर्गत समान वस्तुएं हैं; यह कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा देश से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद अभिलक्षणों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यो एवं प्रकार्यो, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं; यह कि उपभोक्तागण इनका प्रयोग अंतर्निमेय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं तथा दोनों ही वाणिज्यिक एवं प्रविधिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे का विरोध नहीं किया है। जांच के पश्चात, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

14. दि एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली ने अपनी दो अन्य सदस्य कंपनियों अर्थात् मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड की ओर से यह आवेदनपत्र नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष दायर किया है।

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

15. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) यह याचिका एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है जो भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है। इस दो अन्य सदस्य कंपनियों, मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड, जिनका "याचिकाकर्ता कंपनियों" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में उल्लेख किया गया है, ने भी इस समीक्षा के लिए याचिका दायर करने, संबद्ध देश से एनटीसीएफ के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने से संगत वित्तीय सूचना प्रदान कराई है। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा मदुरा इंडस्ट्रियल टैक्सटाइल्स लिमिटेड भी भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रही है।
- (ii) याचिकाकर्ता का जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में अधिकांश उत्पादन पर कब्जा था और इसलिए वे घरेलू उद्योग है। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा के मामले में आधार की जांच करना अपेक्षित नहीं होता है।

- (iii) ग्रुप कंपनियों में से मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड, मैसर्स बिरला टायर्स चीन से शुल्क मुक्त एनटीसीएफ की अल्प मात्रा का नियमित रूप से आयात कर रही हैं। भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का चीन से आयातों की मात्रा मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड के उत्पादन, भारतीय उत्पादन तथा भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत की मात्रा पर विचार करते हुए मैसर्स बिरला टायर्स द्वारा किए गए आयात बहुत कम हैं। इसलिए, प्राधिकारी, मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड को कृपया पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में मान लें।
- (iv) डिबीजनल बेंच कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय दोनों ने अंतिम आदेश जारी कर दिए हैं जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त विवेकाधिकार प्राप्त है।
- (v) ऊपर उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जा सकता है।

घ.2. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

16. घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- (i) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं में से एक इस संबद्ध वस्तु का अपनी संबद्ध कंपनी के जरिए आयात कर रहा है जबकि अन्य याचिकाकर्ता थाईलैंड में एक संबद्ध कंपनी है जो भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रही है।
- (ii) चूंकि याचिकाकर्ताओं का आयातकों या निर्यातकों से संबंध है, इसलिए वे घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के पात्र नहीं हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि वे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदनपत्र एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एसएफआई) (याचिकाकर्ता के रूप में उल्लिखित), जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी दो सदस्य कंपनियों मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड को भी "याचिकाकर्ता कंपनियां" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है, उन्होंने भी इस याचिका को दायर करने से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि आवेदक के अलावा मैसर्स मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड भी भारत में समान उत्पाद का उत्पादन करता है। तथापि, मैसर्स मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड से इस वर्तमान जांच के समर्थन में या उसके विरोध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि प्रतिभागिताकारी कंपनियों के उत्पादन का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

19. प्राधिकारी ने संज्ञान में यह लाया गया है कि मैसर्स बिरला टायर्स, जो मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों में से एक है, चीन से शुल्क मुक्त एनटीसीएफ का अल्प मात्रा में नियमित रूप से आयात कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि मैसर्स बिरला टायर्स द्वारा किए गए आयात की मात्रा, चीन से भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सकल आयात, मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड के उत्पादन और भारतीय उत्पादन तथा भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत पर विचार करते हुए बहुत कम है। यद्यपि यह तर्क दिया गया है कि सेंचुरी एन्का को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाए, यह नोट किया जाता है कि इनमें से किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बिरला टायर्स द्वारा किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। बिरला टायर्स ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को सहयोग करने को अधिमानता दी है। यद्यपि एटीएमए इस वर्तमान जांच में प्रतिभागिता कर रहा है और बिरला टायर्स इसका एक सदस्य है फिर भी एटीएमए ने बिरला टायर्स द्वारा किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस पृष्ठभूमि में मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानना उपयुक्त होगा। यह देखा जाता है कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड का उत्पादन इस जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन का ***% उत्पादन बनता है और इसलिए आवेदक को नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

20. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह याचिका नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार के प्रतिमान को पूरा करता है।

ड. विविध मुद्दे**ड.1. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण**

21. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) याचिका के अगोपनीय पाठ में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा किए गए उल्लेख का विरोधाभासी है। याचिका के विवरणात्मक पाठ में क्षति का कोई दावा नहीं है, जबकि प्राधिकारी ने यह प्रेक्षण किया है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग ने यह निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ कराने के लिए जानबूझकर गलत एवं अधूरी सूचना प्रदान कराई है और बाद में उसे प्रपत्र IV-क में अनुपूरक के रूप में रूप में प्रस्तुत किया है।
- (ii) घरेलू उद्योग की स्थिति अच्छी थी और उसे कोई क्षति नहीं हो रही थी। यह जांच त्रुटिपूर्ण आधार पर शुरू की गई है और संपूर्ण प्रक्रिया अमान्य ठहराई जा सकती है।
- (iii) आवेदकों ने इस संबंध में कोई अकाट्य तर्क नहीं दिए हैं कि संबद्ध देश के संबंध में इस साधन को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन में प्रदान कराए गए साक्ष्य की "पक्षपात रहित और उद्देश्यपरक" जांच से साक्ष्यों की अपर्याप्तता के कारण इस जांच की शुरूआत को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- (iv) आवेदकों ने वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शूलक में विस्तार करने की मांग करने के एकमात्र उद्देश्य से अपने दावे के समर्थन में बिना कोई उपयुक्त साक्ष्य दिए दायर की गई है। तथापि, पाटनरोधी शूलक को जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि भारत ने डब्ल्यूटीओ करार में सिद्धांत यह उल्लेख किया है कि वह इस उपाय का विस्तार 10 वर्षों से अधिक के समय के लिए नहीं करेगा।
- (v) यदि घरेलू उद्योग वास्तव में यह महसूस करता है कि उसे निर्यातों से क्षति हुई है तो वह नई जांच के लिए पर्याप्त साक्ष्यों सहित आवेदनपत्र दे सकता है। एक मूल जांच में पाटन एवं क्षति सिद्ध हुई है। तथापि, एसएसआर में क्षति की केवल संभावना स्पष्ट हुई है।
- (vi) यदि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर के संबंध में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो निर्यातक को यह अधिकार है कि वह अपना प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण दायर करे।
- (vii) आवेदकों ने अपनी सूचना विहित प्रपत्र में प्रेषित की है जो वास्तव में मूल आवेदनपत्र के लिए होता है न कि निर्णायक समीक्षा जांच के लिए।
- (viii) आवेदकों का यह तर्क गलत है कि जांच शुरूआत तब अधिदेशित हो जाता है जब ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है।
- (ix) इस जांच में निर्धारित की गई जांच की अवधि इस तथ्य के मद्देनजर त्रुटिपूर्ण है कि जांच को जांच शुरूआत की समाप्ति की तारीख के यथा-व्यवहार्य निकटतम समय पर समाप्त होना चाहिए।
- (x) आवेदकों ने अपनी एनसीवी याचिका में पर्याप्त सूचना के संबंध में गोपनीयता का आश्रय लेने के लिए किसी संतोषजनक कारण का उल्लेख नहीं किया है।
- (xi) आवेदकों का यह दावा उपयुक्त नहीं है कि निर्णायक समीक्षा की जांच कतिपय प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य है। आवेदकों ने अपने इस तर्क के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है। तथापि, उद्धृत किए गए इन निर्णयों के उपरांत पाटनरोधी नियमावली में कुछ संशोधन किए गए हैं और इसलिए इस समीक्षा की शुरूआत करना संबद्ध वस्तु की मौजूदगी और पर्याप्त आधार के संबंध में शर्तों को पूरा करने पर ही प्रासंगिक रूप से किया जा सकता है।
- (xii) आवेदकों का यह दावा है कि निर्णायक समीक्षा में पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच करने के लिए कोई क्रियापद्धति विहित नहीं है, और इसे उक्त प्रक्रिया के संगत प्रावधानों की मौजूदगी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अस्वीकार किया जा सकता है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) निर्यातक की प्रश्नावली सकल रूप से ही त्रुटिपूर्ण है कि घरेलू उद्योग उसका प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं है।
- (ii) मूल जांच तथा निर्णायक समीक्षा जांच दोनों का दायरा पूर्णतया भिन्न-भिन्न है। यदि इस उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षतिकारित कर रहा है तो नई याचिका दायर की जा सकती है। तथापि, निर्णायक समीक्षा का दायरा यह है कि क्या पाटनरोधी शूलक को समाप्त कर देने से पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की

संभावना है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार स्वतः इस तथ्य से सहमत है कि निर्णायक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी से क्षति की संभावना की जांच करना अपेक्षित होता है। ऐसा होते हुए भी, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के नोटिस में वास्तविक क्षति का उल्लेख किया है।

- (iii) शुल्क मुक्त आयात भी घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं और इसलिए उस मात्रा का अपवर्जन करने का कोई औचित्य नहीं है।
- (iv) निर्णायक समीक्षा जांच को दायर करने के लिए कोई विहित प्रपत्र नहीं है। उसके अभाव में, याचिकाकर्ताओं ने नए आवेदनपत्र के प्ररूप में आवेदन किया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने निम्नलिखित जांच की है :

- (i) प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण पाटनरोधी अधिनियम, नियमावली और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के आधार पर किया गया है।
- (ii) यह तर्क दिया गया है कि जांच शुरूआत अधिसूचना क्षति के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के विपरीत है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांचों की शुरूआत घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर की है जैसा कि जांच शुरूआत नोटिस से स्पष्ट है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरूआत के इस नोटिस को संपूर्णता में पढ़े जाने की अपेक्षा है, न कि एकान्तता में।
- (iii) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में कई अन्य कारकों के आधार पर सुधार हुआ है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, प्राधिकारी पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने पर विचार करने के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की संभावना है या नहीं।
- (iv) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं कराए हैं कि शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को किस तरह क्षति होगी, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि याचिका में इस संबंध में संगत जानकारी दी गई है और वर्तमान निर्धारण पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संबंध में संगत साक्ष्य के आधार पर किया गया है।
- (v) जहां तक डब्ल्यूटीओ के समक्ष भारत सरकार द्वारा अभिव्यक्त इस विचार का संबंध है कि 10 वर्षों की अवधि के पश्चात इस उपाय को जारी नहीं रखा जाएगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो डब्ल्यूटीओ द्वारा ऐसा कोई निर्णय किया गया और न ही भारतीय विधि में ऐसा कोई संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान हो कि पाटन की संभावना बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने पर भी 10 वर्षों की अवधि के पश्चात पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करना चाहिए। भारतीय नियमों में यह प्रावधान है कि किसी समीक्षा में केंद्रीय सरकार का यदि यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बनती है तो वह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि में अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार कर सकती है और इसकी अतिरिक्त अवधि ऐसे समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी। अतः, यदि जांच से यह दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाने पर पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना बनी रहेगी तो पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।
- (vi) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग नई याचिका दायर कर सकता है और वर्तमान शुल्क को समाप्त किया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नई याचिका का दायरा निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे से पूर्णतया भिन्न है। एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी से यह निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या उक्त शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जबकि नवीन जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या विचाराधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया जा रहा है, और क्या उक्त वस्तु के आयातों से भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है या वास्तविक क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना की प्रगति में वस्तुतः अवरोध उत्पन्न कर रही है और क्या पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। इस प्रकार निर्णायक समीक्षा का दायरा नई जांच के दायरे से पूर्णतया भिन्न है। किसी भी हाल में, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को नवीन याचिका दायर करने का अधिकार है, घरेलू उद्योग को निर्णायक समीक्षा जांच की मांग करने से वारित नहीं करता है।
- (vii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यह याचिका ऐसे ढंग और स्वरूप में दायर की गई है जो मूल जांच के लिए निर्धारित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस याचिका में नवीन मामले के लिए निर्धारित सभी संगत सूचना के अलावा पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में सभी संगत सूचना का उल्लेख है।

- (viii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग का निर्णायक समीक्षा को अधिदेशित प्रकृति के संबंध में किया गया दावा गलत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मौजूदा निर्धारण पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित है।
- (ix) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इस जांच के लिए निर्धारित की गई जांच की अवधि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए त्रुटिपूर्ण है कि यह जांच यथाव्यवहार्य, जांच शुरूआत की समाप्ति की तारीख के निकटतम तारीख को समाप्त होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच के लिए निर्धारित जांच अवधि इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उपयुक्त एवं तर्कसंगत है। किसी भी हाल में, रिकार्ड में यह दर्शाने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी अन्य पर्याप्त अवधि पर विचार करने से कोई बहुत अधिक भिन्न निष्कर्ष निकल सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि जांच की अवधि जांच की शुरूआत की तारीख की निकटतम अवधि को समाप्त होनी चाहिए।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

24. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- क) चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी भी डब्ल्यूटीओ देश ने डब्ल्यूटीओ विधि में विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया और जांच के पश्चात चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा प्रदान नहीं किया है। चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने का दावा नहीं किया है। वास्तव में चीन के केवल एक निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और चीन के अन्य किसी उत्पादक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी दायर नहीं किया है। चीन का केवल एकमात्र निर्यातक जिसने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है, वह मैसर्स जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड है, उसने भी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है। अतः, किसी भी हाल में, बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा देने पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नियमों में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की जांच केवल तभी करेंगे जब चीन के उत्पादकों द्वारा उसके लिए विधिवत साक्ष्यांकित दावा किया जाएगा।
- ख) पिछली जांच में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मैसर्स निंग्बो नायलान कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और मैसर्स निंग्बो जिल्लुन आयात एवं निर्यात कंपनी लिमिटेड (संबद्ध निर्यातक) को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया था। नियम 7 के अनुसार सामान्य मूल्य पर विचार किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, नियमों में इस संबंध में विशिष्ट अनुक्रम का निर्धारण किया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उसका ही अनुसरण किया जाना चाहिए। नियमों में तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अथवा लागत पर विचार करने का प्रावधान भी है।
- ग) याचिकाकर्ता ने थाईलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तृतीय देश माना है। थाईलैंड चीन के लिए निम्नलिखित कारणों से एक उपयुक्त सरोगेट देश है :
- थाईलैंड में एक से अधिक घरेलू उत्पादक हैं और इसलिए वहां की बाजार प्रतिस्पर्धात्मक है।
 - थाईलैंड में इस उत्पाद का भारी मात्रा में आयात होता है। इससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि थाईलैंड में भारी प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी है।
 - थाईलैंड को एक उपयुक्त सरोगेट देश मानने के लिए प्रमुख कारणों में से एक कारण सभी संगत सूचना की उपलब्धता है।
 - अंतर्ग्रस्त उत्पाद प्रकार तुलनीय है।
 - चीन ने भारत को ग्रीग और डिण्ड फेब्रिक का निर्यात किया है। डिण्ड फेब्रिक का उत्पादन ग्रीग फेब्रिक से किया जाता है। थाईलैंड के उत्पादक थाईलैंड में ग्रीग और डिण्ड फेब्रिकों का उत्पादन करते हैं और इसलिए उत्पाद प्रकार पूर्णतया तुलनीय है। याचिकाकर्ता में भारित औसत तुलना का आश्रय नहीं लिया है। याचिकाकर्ता ने ग्रीग फेब्रिक की कीमतों की तुलना ग्रीग फेब्रिक की लागत से करने का आश्रय लिया है।
- घ) तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने थाईलैंड में ग्रीग और डिण्ड फेब्रिक की फैक्टरी बाह्य विक्री कीमत का निर्धारण किया है और उसे ही याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अपनाया है।
- ङ) प्रतिवादी निर्यातक, जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड ने भारत में एफओबी कीमत से केवल समुद्री भाड़ा और सामुद्रिक बीमे पर हुए व्यय की रिपोर्टिंग करने के पश्चात निर्यात कीमत का दावा किया है। निर्यातक यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने अपने उत्पाद का निर्यात उन अन्य व्ययों को उपगत किए बिना कैसे किया है जबकि चीन से निर्यात के संबंध में तो यह एक सामान्य घटना है।

- च) याचिकाकर्ताओं ने ग्रीग और डिण्ड उत्पाद के लिए, दोनों की लागत और कीमत में भारी अंतर को देखते हुए, अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और यह न्यूनतम स्तर से अधिक है।
- छ) अगर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो संबद्ध देश के उत्पादक/ निर्यातक और अधिक पाटन करना प्रारंभ कर देंगे।

च.2. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (i) जियांग्सु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए आवेदन नहीं किया है। वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य को स्वीकार कर सकते हैं।
- (ii) संबद्ध देश से आयात "शुल्क मुक्त" साधन के अध्यधीन किया जा सकता है और इस कारण उसे किसी मात्रा क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ संबंध वस्तु की कुल मात्रा से अपवर्जित किया जा सकता है। चूंकि चीन से आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत होते हैं, और इस कारण वह घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं कर सकता है, और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए इन निर्यातों पर विचार करना उचित नहीं है।
- (iii) आवेदकों द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है।
- (iv) निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य को आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अनुचित निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य का प्रकटन नहीं किया गया है और यूएस डालर 0-10 की रेंज प्रदान कराई गई है जो किसी तर्कसंगत समझ के प्रयोजनार्थ बहुत व्यापक है।
- (v) सामान्य मूल्य का निर्धारण थाईलैंड के आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया है। आवेदकों ने थाईलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था मानने के लिए चयन करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं दिया है। चीन और थाईलैंड के बीच एनटीसीएफ की उत्पादन लागत के आधार पर अथवा प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर अर्थात् दोनों देशों में घरेलू खपत के आधार पर तुलना करने का सामान्यतया कोई आधार नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों में भी भारी अंतर है जैसाकि आवेदकों द्वारा भी स्वीकृत किया गया। अतः, भारित औसत आधार पर किया गया कोई भी विश्लेषण त्रुटिपूर्ण और प्रयोज्य न होने वाला होगा।
- (vi) इसके अतिरिक्त, यह भी दावा किया है कि थाईलैंड में पारिश्रमिक की दर चीन में पारिश्रमिक की दर की तुलना में 30-50 प्रतिशत अधिक है और संबद्ध वस्तु के संबंध में चीन में प्रचालन की दर थाईलैंड की तुलना में लगभग 30 गुनी अधिक है। अतः चीन में संपरिवर्तन लागत बहुत न्यूनतर है।
- (vii) थाई बड़ोदा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसे एसआरएफ द्वारा अवाप्त कर लिए जाने से पहले एक रूग्ण इकाई थी और इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रचालन लागत बहुत अधिक है।
- (viii) ताईवान के उत्पादकों की कतिपय लागतों का ग्रीग फेब्रिक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु प्रयोग किया गया है और इस सामान्य मूल्य को थाईलैंड में प्रचालित सामान्य मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (ix) ऐसा प्रतीत होता है कि थाईलैंड के उत्पादक ग्रीग फेब्रिक की बिक्री नहीं करते हैं और इसलिए इसका आशय यह है कि थाईलैंड चीन की तुलना में प्रश्नाधीन वस्तु के उत्पाद के संबंध में इतना अधिक विकसित नहीं है कि वह चीन की समानता कर सके।
- (x) प्रत्येक जांच में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक निर्यातक को नए सिरे से बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण किया जाए और इसका विगत की जांचों में निर्धारण लिए बिन्दुओं से की जाए।
- (xi) मैसर्स जुन्मा टायर कार्ड कंपनी लिमिटेड, निंग्बो नायलान कंपनी लिमिटेड, हुसैन नायलान कैमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड और निंग्बो जिनलुन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने उनके द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर में बाजार अर्थव्यवस्था का दावा किया है। इन पक्षकारों ने पुनः यह दावा किया है कि पाटन मार्जिन का परिकलन उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर की गई।
- (xii) आयातों का भारी मात्रा में आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किया गया था और उस पर कोई पाटनरोधी शुल्क भी नहीं लगा था। शुल्क मुक्त कीमत के अंतर्गत किए गए सभी संव्यवहारों को "निर्यात" कीमत का निर्धारण करने के लिए किया जाए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रतिवादी निर्यातक की घरेलू बिक्री लागत पर विचार करना चाहिए, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण उसकी घरेलू कीमतों पर बाजार कीमतों का विमर्शक होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप, केवल जिआंग्सु हाययांग कैमिकल फाइवर्स कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है परंतु उसने बाजार अर्थव्यवस्था दर्ज प्रश्नावली दायर नहीं की है। चीन के प्रतिवादी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत चीन वर्षों में चीन जन.गण. भारत द्वारा और डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों द्वारा किसी भी पाटनरोधी जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में नियमों में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप निर्यातक राष्ट्र या किसी व्यक्तिगत निर्यात द्वारा उक्त धारणा के खंडन के अध्यधीन माना गया है।

28. यथासंशोधित नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश की पूर्वाधारणा का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिमान के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं। चीन में संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित प्रतिमान का अनुपालन इस तथ्य पर विचार करते हुए कर सके कि क्या :

- क. उक्त देश में कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्रियों और निवेश को शामिल करते हुए कीमत लागत और इनपुट के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए गए हैं जो मांग एवं आपूर्ति को प्रतिबिंबित करते हैं और इस संबंध में निर्णय राज्य के हस्तक्षेप के बिना किया गया है और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत बाजारों मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है;
- ख. इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, बट्टे खातों में डाले गए अन्य, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति द्वारा भुगतान से की गई भारी विकृतियों के अध्यधीन होती है।
- ग. यह फर्मों दिवालियापन और संपत्तियों विधियों के अध्यधीन होती है जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता एवं स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है; और
- घ. विनिमय दर परिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

29. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स जिआंग्सु हायांग कैमिकल फाइवर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ही चीन जन.गण. की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। इस कंपनी ने अपेक्षित बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी अन्य उत्पादक एवं निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत नोटिस जारी किए जाने के परिणामस्वरूप निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अवधारणा का खंडन किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की प्रतिवादी कंपनियों द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन किए जाने के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुरूप आगे बढ़ना उचित समझते हैं।

30. जहां तक चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु थाईलैंड को उपयुक्त देश के रूप में विचार करने को घरेलू उद्योग के दावे का प्रश्न है, प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने चीन, संबद्ध देश के लिए थाईलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चयन करने के लिए पर्याप्त कारण/सूचना प्रदान नहीं कराई है। प्राधिकारी का विचार है कि चीन में समग्र आर्थिक विकास के उच्चतर स्तर पर और चीन में संबद्ध उत्पाद के संबंध में उत्पादन लागत, क्षमता और निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए चीन और थाईलैंड को तुलनीय के रूप में मानने को उचित नहीं समझते हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य की संरचना करने हेतु उपयुक्त देश के रूप में भारत को अपनाए जाने का प्रस्ताव किया है।

च.4. सामान्य मूल्य का निर्धारण

31. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में यह इंगित किया था कि याचिकाकर्ता ने चीन के लिए सामान्य मूल्य की संरचना भारत में उत्पादन लागत के आधार पर उसमें नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का समायोजन सहित विधिवत समायोजित करके किए जाने का दावा किया है। तथापि, आवेदकों और चीन के उत्पादकों सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई भी वास्तविक तथ्य, इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के रूप में चयन करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि भारत को इस मामले में चीन के लिए एक उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग के इस दावे का किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया है।

32. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। तदनुसार चीन जन.गण. में सभी निर्यातकों के लिए इस विचाराधीन उत्पाद की फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य की संरचना प्रमुख इनपुटों, अर्थात् कैपरोलेक्टम (सीपीएल) नायलान-6 चिप्स, यार्न, स्कैप, अनुषंगी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार किया है जिसका घरेलू उद्योग द्वारा अन्य कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के खपत मानकों संपरिवर्तन लागत और एसजीए व्ययों को अपनाया गया है। प्राधिकारी ने 5 प्रतिशत का तर्कसंगत लाभ मार्जिन जोड़ने के पश्चात् चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना अधोलिखित पाटन मार्जिन में दर्शाए गए के अनुसार की है।

च.5. निर्यात कीमत का निर्धारण

मैसर्स जियांग्सु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स जियांग्सु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने ही विहित स्वरूप और ढंग से प्रत्युत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने, प्रहस्तन प्रभार, समुद्रपारीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, बैंक प्रभार और वैंट समायोजन, जैसाकि निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में दावा किया था, के आधार पर फैक्टरी बाह्य निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समायोजन किया है। तदनुसार मैसर्स जियांग्सु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के लिए निवल निर्यात कीमत का फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारण किया है, जिसे अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोग निर्यातक

34. जहां तक असहयोगकर्ता निर्यातकों का संबंध है, यह नोट किया गया कि सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा निर्यात की जा रही निर्यातों की मात्रा संबद्ध देश से होने वाले कुल आयातों का *** प्रतिशत है और इसलिए, वह कुल आयातों का प्रतिनिधिक न होने के कारण पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए "उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यूनतम निर्यात कीमत को लिया गया है। फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत पर पहुंचनों के लिए समुद्री मालभाड़ा, बैंक प्रभार, वैंट आदि जैसे समायोजनों की अनुमति दी गई है। इस प्रक्रिया को अपनाकर संबद्ध वस्तु के लिए असहयोगकर्ता निर्यातकों के बारे में फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारण किया गया है जिसका उल्लेख अधोलिखित पाटन मार्जिन में किया गया है।

च.6. पाटन मार्जिन

35. पिछले पैराग्राफों में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करके प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन का निम्नवत निर्धारण किया गया है :

विवरण	मैसर्स जियांग्सु हाययांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	असहयोगकर्ता निर्यातक
भारित औसत सामान्य मूल्य यूएस डालर/किलोग्राम	***	***
निर्यात कीमत यूएस डालर/किलोग्राम	***	***
पाटन मार्जिन - यूएस डालर/किलोग्राम	***	***
पाटन मार्जिन - %	***	***
पाटन मार्जिन रेंज- %	10-20	35-45

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का आकलन

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

36. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- क. जांच की अवधि में थोड़ी सी कमी को छोड़कर मांग में संपूर्ण क्षति अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।
- ख. इस संबद्ध वस्तु के चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष से लेकर वर्ष 2012-13 तक समग्र रूप से धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में यह आयात आधार वर्ष में हुए अनुपात की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में कुल आयात, उत्पाद और खपत के संगत रूप से वृद्धि हुई है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारी कीमत अधोरदन हुआ है।

- घ. पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से बहुत कम है। आयातों की उतराई कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दोनों में समान वृद्धि एवं गिरावट हुई है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क युक्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न तो निग्रहण कर रहे हैं और न ही अवमंदन। पाटनरोधी शुल्क लगे होने की स्थिति में आयात कीमतें भारत में तर्कसंगत रूप से बेहतर कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभावी पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को क्षति से वंचित कर रखा है।
- ङ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा इसके समान ही बना रहा जबकि क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- छ. लाभप्रदता में वर्ष 2011-12 में गिरावट आई और फिर वर्ष 2012-13 में इसमें वृद्धि हुई तथा फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता इस अवधि में स्थिर बनी रही।
- ज. घरेलू उद्योग ने कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ ने लाभ के अनुरूप ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। कीमत प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिर स्थिति प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की परावर्तक है।
- झ. घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई है और फिर इसमें गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में यह मालसूची बहुत अधिक बनी रही।
- ञ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के अनुभव ही उतार-चढ़ाव आया है। सामान्यतः क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता कमोवेश रूप से स्थिर बनी रही।
- ट. चीन जन.गण. के संबंध में परिकलित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।
- ठ. बिना पाटनरोधी शुल्क के आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन करेंगे और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अवमंदन प्रभाव होगा।
- ड. क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह आदि के संबंध में घरेलू उद्योग को वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण निरंतर क्षति नहीं हुई है, जिसने संबद्ध देश की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के प्रतिवारक के रूप में काम किया।
- ढ. भारत चीन के निर्यातकों के लिए इस संबद्ध वस्तु की सबसे बड़ी निर्यात बाजार है। यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो संबद्ध देश के उत्पादक और निर्यातक भारत में अपना पाटन तीव्र कर देंगे।
- ण. चीन से तृतीय देशों को निर्यात भारत को चीन के निर्यातों की तुलना में अत्यधिक उच्चतर कीमतों पर किए जाते हैं। इससे स्पष्टतः यह प्रदर्शित होता है कि चीन के उत्पादक भारतीय बाजार में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री करने में सक्षम है। पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के कारण यह कीमतें घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा पा रही हैं। तथापि, यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो यह कीमतें घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित करना प्रारंभ कर देंगी।
- त. पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने से पाटन और अधिक तीव्र हो जाएगा क्योंकि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद वर्ष 1999-2000 से भारी मात्रा में पाटन बना हुआ है।
- थ. पाटनरोधी शुल्क के बिना आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं। इसलिए उपभोक्तागण आयातित उत्पाद की ओर मुड़ गए हैं और यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है तो इससे इस उत्पाद का भारी मात्रा में आयात होना शुरू हो जाएगा।
- द. यदि घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में बाजार में कमी आ जाती है तो उससे घरेलू उद्योग की बिक्री में भी कमी आ जाएगी।
- ध. यदि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आ जाती है कि इसका उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग घटेगा। अतः, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से घरेलू बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- न. यदि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात अपनी कीमतें कम करके चीन की प्रतिस्पर्धा का प्रत्युत्तर देता है तो इसका आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग पर भारी विपरीत कीमत प्रभाव पड़ेगा। यदि घरेलू उद्योग चीन की कीमतों से तुलनीय कीमतों पर बिक्री करता है तो घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत भी पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा और इस प्रकार उसे भारी वित्तीय घाटा, ऋणात्मक नकद प्रवाह और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ होगा।
- प. क्रेता अपने प्रापण का निर्णय विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई संगत कीमतों के आधार पर करते हैं। यदि विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतें सस्ती हैं, तो क्रेतागण विदेशी उत्पादकों से अधिक खरीद करने लगेंगे।

- मौजूदा मामले में यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश के निर्यातक भारत में अपनी उच्च उत्पादन क्षमता एवं न्यून निर्यात कीमतों को देखते हुए और अधिक बाजार पर कब्जा कर लेंगे।
- फ. पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों के और अधिक तीव्र होने की संभावना है।
- ब. पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- भ. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के अनुरूप करना अपेक्षित है।
- म. घरेलू उद्योग एनटीसीएफ के सीटीसी ग्रेड का भी विनिर्माण करता है जिसका प्रयोग साइकल टायर के विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान इस ग्रेड के आयात नहीं हुए हैं।
- य. इस साधन का स्वरूप नियत प्रमात्रा में रखना अपेक्षित है।

छ.2. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

37. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं।

- क. कोई भी आर्थिक पैरामीटर यह नहीं दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ख. घरेलू उद्योग ने तर्कयुक्त एवं न्यायोचित औचित्य युक्त कोई तथ्यात्मक आधार प्रदान नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।
- ग. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के दौरान अच्छा लाभ अर्जन हुआ है। प्रति शेयर अर्जन असामान्य रूप से भारी है जैसाकि एसआरएफ के टीटीवी सेगमेंट के सेगमेंट परिणामों और सेंचुरी एन्का की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है।
- घ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है क्योंकि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में इसकी लाभप्रदता में और अधिक वृद्धि हुई।
- ङ. निर्यातकों ने उस आधार और आंकड़ों की मांग की है जिन पर प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष निकालने पर भरोसा किया।
- च. यदि घरेलू उद्योग ऐसा वास्तव में लगता है कि उसे निर्यातकों से नुकसान हुआ है तो वह जांच के लिए नया आवेदन पत्र कोई पर्याप्त साक्ष्य देकर प्रस्तुत कर सकता था। मूल जांच में पाटन एवं क्षति को सिद्ध करना था। तथापि, एसएसआर में क्षति की केवल संभावना को सिद्ध किया जाता है।
- छ. आवेदकों के दावे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। एक ओर तो वे यह दावा करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति अच्छी है, वहीं दूसरी ओर वे दावा करते हैं कि घरेलू उद्योग उचित विक्री कीमत वसूल करने में सक्षम नहीं रहा।
- ज. यह आवेदक विरोधाभासी दावों से भरा पड़ा है। एक ओर तो मांग में कमी को आटोमोबाइल उद्योग में मंदी पर उपरोपित की गई है, जबकि दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि मांग में कोई नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है।
- झ. मांग में गिरावट केवल यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया क्षमता विस्तार की मांग में प्रत्याशित वृद्धि के कारण गलत संगणना की गई है। इस कारण होने वाली क्षति को आयातों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है।
- ञ. शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर विचाराधीन उत्पाद का कीमत अवमंदन या निग्रहण होना, आवेदकों को कोरी कल्पना है।
- ट. आवेदकों ने यह उल्लेख किया है कि चीन इस संबद्ध वस्तु का भारत को सर्वाधिक निर्यात करता है, क्योंकि भारत इसकी वस्तु की विक्री करने के लिए सबसे ज्यादा "आकर्षक बाजार" है। तथापि, आवेदकों के इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य या स्रोत नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े स्वतः ही स्पष्टतः यह दर्शाते हैं कि चीन के निर्यातक भारत केंद्रित नहीं रहे हैं और इसलिए आवेदकों द्वारा इस संबंध में किया गया दावा गलत है।
- ठ. विदेशी उत्पादकों की मुक्त रूप से निस्तारणीय मौजूदा एवं संभावित क्षमताओं से उनकी यह प्रतिबद्धता तो प्रदर्शित नहीं होती है कि वे अपने इस तरह से उत्पादित संबद्ध वस्तु की विक्री भारत को ही करेंगे।
- ड. चीन से भारत को निर्यात कीमत अन्य देशों को निर्यात कीमत की तुलना में कम है क्योंकि यह संबंधित बाजार में मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर की स्थिति पर निर्भर होती है।

- ढ. घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति पाटन के कारण न होकर अन्य कारणों से हुई है जिनमें खपत की प्रणाली में परिवर्तन तथा घरेलू उद्योग का निर्यात के प्रति झुकाव शामिल है। आवेदकों ने उनको असुविधाकर आंकड़े जान बूझकर न देने का चयन किया है।
- ण. एक अन्य घरेलू उत्पादक मुद्रा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल लिमिटेड ने अभी हाल ही में भारत में एनटीसीएफ का उत्पादन करना शुरू किया है और उसने लगभग 20000 एमटी की क्षमता संस्थापित की है। इसलिए उसको हुई क्षति घरेलू उद्योग उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।
- त. घरेलू उद्योग को लगातार क्षति नहीं हो रही है। संबद्ध देशों से आयात की सीआईएफ कीमत में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में कमी आई है।
- थ. आवेदकों द्वारा यथा-दावाकृत क्षति सहन करने वाला उद्योग प्रतिवर्ष अपनी क्षमताओं में विस्तार नहीं कर सकता है, जैसाकि आवेदकों द्वारा किया गया है। वास्तव में घरेलू उद्योग के निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है।
- द. आवेदक यह सिद्ध करने के लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य देने में असफल रहे हैं कि शुल्क की समाप्ति से क्षतिकारी पाटन की पुनरावृत्ति होगी। आवेदकों का यह तर्क कि चीन के इस संबद्ध वस्तु के निर्यातकों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, इसके बारे में कोई ऐसा स्रोत नहीं दिया गया जिसके कारण इस सूचना की सच्चाई का पता लगाया जा सके और उसकी पुष्टि की जा सके।
- ध. आवेदक में पाटन एवं कथित क्षति की संभावना से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इन दोनों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है और इस आवेदन को असंगत होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- न. कूड एवं पेट्रोलियम उत्पादों में 130 यूएस डालर से कमी होकर 40 यूएस डालर हो गए हैं। अपनाई गई पीओआई को पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए पैरोमीटर नहीं माना जा सकता है अथवा पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण संबद्ध वस्तु की कीमतों में समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए यथामूल्य आधार पर अधिरोपित की जानी चाहिए।
- प. चीन के आयातों की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में 8 प्रतिशत की कमी आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन के निर्यातों ने अपना बल अन्य बाजारों पर देना भी शुरू कर दिया है। चीन के निर्यात से संबंधित सूचना का स्रोत आवेदकों द्वारा प्रदान नहीं कराया गया है।
- फ. आवेदकों का संयंत्र 20 वर्ष से अधिक पुराना है जिससे उसकी लागत अधिक हो जाती है और वह अप्रतिस्पर्धी बन जाता है। प्राधिकारी को उनकी उच्चतर गैर-क्षतिकारी कीमत का दावा नामंजूर कर देना चाहिए।
- ब. आवेदकों का अच्छा निष्पादन पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण नहीं हुआ है बल्कि ढांचागत परिवर्तनों, प्रचालनों में कमी को समाप्त करने और उनके द्वारा किए गए नए निवेश के कारण हुआ है।
- भ. चीन से आयातों की उतराई कीमत में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से उनकी भारत को बिक्री कीमत में और अधिक वृद्धि होगी जिससे कि वे अपना मार्जिन बढ़ा सकें।
- म. उपर्युक्त के मद्देनजर किसी तरह की क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों को नोट किया है और उन तथ्यों पर रिकार्ड में उपलब्ध तथा लागू विधि के अनुसार विचार किया है। जहां तक विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन और तथ्यों एवं आंकड़ों से संबंधित मुद्दे का प्रश्न है, उसका निराकरण क्षति विश्लेषण में तथ्यतः कर दिया गया है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई है और उनका निम्नवत समाधान किया गया है :

- क. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और कई आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार प्रदर्शित हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी को केवल क्षति की संभावना का निर्धारण करने की ही जरूरत होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी को पहले तो यह सुनिश्चयन करना होता है कि क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है; और यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित होता है। मौजूदा निर्धारण चालू अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति की जांच और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच पर आधारित है।
- ख. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के बाद की सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी विचार करते हैं कि पोस्ट पीओआई से संबंधित सूचना केवल ऐसी स्थिति में ही संगत है जहां घरेलू उद्योग को चालू पीओआई में क्षति न हुई है और पीओआई के लिए सूचना पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना

प्रदर्शित न करती हो। यदि पीओआई के लिए सूचना पाटन एवं क्षति तथा घरेलू उद्योग को पाटन एवं/या क्षति की संभावना दर्शाती हो वहां प्राधिकारी को पीओआई के पश्चात के आंकड़ों पर विचार करना अपेक्षित नहीं होता है। वर्तमान जांच में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई में भारी मात्रा में पाटन एवं क्षति मार्जिन दर्शाई गई है क्योंकि चीन से आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की एनआईपी से बहुत कम है और इसलिए प्राधिकारी को पोस्ट-पीओआई आंकड़ों की जांच करना अपेक्षित नहीं है।

- ग. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पाद की मांग में गिरावट के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण में संगत स्थान पर तथ्यात्मक स्थिति की जांच की है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता देश में इस उत्पाद की मांग की तुलना में कम है और इसलिए इस मामले के तथ्य यह नहीं दर्शाते हैं कि देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- घ. मुक्त रूप से निस्तारणीय मौजूदा एवं संभावित क्षमताओं के संबंध में साक्ष्य के अभाव के संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में किया गया निर्धारण दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस संबंध में चीन के निर्यातकों द्वारा प्रेषित प्रश्नावली प्रत्युत्तर की जांच की है। किसी भी हाल में यह स्पष्ट है कि पीओआई के दौरान चीन से आयातों की मात्रा 29461 एमटी थी और यह भारत में इस उत्पाद की मांग का 21.01 प्रतिशत है। अतः, आयातों की मौजूदा मात्रा स्वतः ही बहुत अधिक है और वह शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्षति की संभावना को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
- ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चीन के अन्य देशों को किए गए निर्यातों की निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वह कीमत जिस पर वस्तु का भारत को निर्यात किया जा रहा है मौजूदा मामले में क्षति की संभावना को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
- च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य घरेलू उत्पादक, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के कारण भी हो सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में एटीएमए ने प्रयोक्ता उद्योग एसोसिएशन के रूप में भाग लिया है और याचिकाकर्ताओं ने उन कंपनियों को बिक्री की है जो एटीएमए की सदस्य हैं। एटीएमए ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया है कि मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल की बिक्री कीमत चीन से आयात कीमत की तुलना में कम है। अतः, यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के कारण हुई होगी। पुनश्च, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इसलिए, यह वह मामला नहीं है जहां दावाकृत क्षति मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के कारण हो रही हो।
- छ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने क्षति की संभावना को स्पष्ट करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर क्षति का दावा किया है :
- (i) चीन के उत्पादक घरेलू बिक्री में गिरावट की भरपाई करने के लिए निर्यात बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
 - (ii) चीन के निर्यातकों के लिए भारत इस संबद्ध वस्तु की सबसे बड़ी बाजार है।
 - (iii) विगत जांच एवं मौजूदा जांच में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।
 - (iv) आयातों की मात्रा मूल जांच अवधि पर आधारित है।
 - (v) विदेशी उत्पादकों की मुक्त रूप से निस्तारणीय मौजूदा एवं संभावित क्षमताएं।
 - (vi) इस उत्पाद और भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के रूप में घरेलू उद्योग की सुभेद्यता।
 - (vii) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता।
 - (viii) साधन के अभाव में कीमत अधोरदन।
 - (ix) यदि एक भी शर्त पूरी होती है तो शुल्क का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है।
- ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि शुल्क में विस्तार करने के लिए पाटन एवं क्षति दोनों की ही संभावना को सिद्ध किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने मौजूदा मामले में पाटन एवं क्षति दोनों ही संभावनाओं की जांच की है।
- झ. जहां तक कूड एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में जांच की अवधि के पश्चात गिरावट होने का संबंध है, यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी पाटन एवं क्षति और/या पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की जांच पीओआई के दौरान प्रचलित पैरामीटरों के आधार पर करते हैं। केवल ऐसी स्थिति में ही प्राधिकारी पोस्ट पीओआई पैरामीटरों पर विचार करते हैं जहां पीओआई के दौरान निष्पादन पाटन एवं क्षति और/या पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति नहीं दर्शाते हैं।

- ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पीओआई में चीन से आयातों में गिरावट आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मौजूदा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और पीओआई के दौरान आयातों की मात्रा ही घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति और/या पाटन एवं क्षति की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।
- ट. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के संयंत्र दो दशक से अधिक पुराने हैं जिसके कारण अधिक लागत आ रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उनकी उत्पादन लागत बहुत कम है क्योंकि उनके संयंत्र पूर्णतया ह्रासित हैं और घरेलू उद्योग को नगण्य ब्याज लागत वहन करनी पड़ती है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने एनआईपी का निर्धारण करने के लिए मौजूदा मूल्य पर विचार करने का तर्क दिया है।
- ठ. जहां तक आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान पीओआई में आयात कीमत में वृद्धि होने का संबंध है, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी संभावना का निर्धारण पीओआई के दौरान प्रचलित कीमत पर की गई है।

छ.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

39. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों के संबंध में प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति के पहलू की संभावना की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई, की जांच करते हैं।

40. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्गस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो । ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए " कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा पर विचार करने में यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है या इन आयातों के प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है, जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

41. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उन सभी तत्वों पर विचार किया गया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन।

42. मौजूदा जांच पहले से प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित विचार करते हुए किया है। पुनश्च, चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही प्रभावी है, इसलिए प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग के निष्पादन में एक या अधिक प्रचालनों के संबंध में सुधार चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण हुआ है। प्राधिकारी ने यह जांच की गई है कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क उस पाटन का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है जो क्षति कारित कर रहा है।

43. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले से ही प्रतिसंहरण नहीं कर दिया गया तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, एक समीक्षा में, का यह विचार न हो कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में यह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण का अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए समय विस्तार करती रहेगी और इस तरह बड़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

44. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की घरेलू उद्योग पर मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच की है और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा क्षति की मौजूदगी की जांच कीमत एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी ने मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एन्का लिमिटेड, जो नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं के संबंध में सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

क. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(क) मांग एवं बाजार हिस्सा

45. प्राधिकारी ने मांग अथवा देश में इस उत्पाद की स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में की है। इस तरह आकलित मांग को अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है। यह देखा जाता है कि देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2012-13 में वृद्धि हुई और पीओआई में इसमें कुछ गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में मांग बढ़ी है। घरेलू उद्योग की बिक्री तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी सुधार हुआ तथापि, चीन से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

भारत में मांग और बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि*
भारत में मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	62,995	64,879	66,745	66,505
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	4,200	4,200	4,200	4,200
संबद्ध देश से आयात	एमटी	23,120	28,631	31,909	29,461
आयात – अन्य देश	एमटी	44,529	38,344	40,821	40,038
आकलित मांग	एमटी	1,34,844	1,36,054	1,43,676	1,40,203
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	46.72	47.69	46.46	47.43
अन्य भारतीय उत्पादक	%	3.11	3.09	2.92	3.00
संबद्ध देश	%	17.15	21.04	22.21	21.01
अन्य देश	%	33.02	28.18	28.41	28.56

*जांच की अवधि - अक्टूबर 2012 से सितम्बर, 2013

(ख) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

46. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत से समग्र रूप से या संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात तथा आयात मात्रा अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि*
चीन जन.गण.	एमटी	23,120	28,631	31,909	29,461
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	124	138	127
अन्य देश	एमटी	44,529	38,344	40,821	40,038
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	86	92	90
कुल आयात	एमटी	67,649	66,975	72,730	69,498
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	99	108	103
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात :					
• कुल आयात	%	34.18%	42.75%	43.87%	42.39%
• उत्पादन	%	36.16%	44.01%	47.99%	44.11%
• खपत	%	17.15%	21.04%	22.21%	21.01%

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष से वर्ष 2012-13 तक समग्र रूप से वृद्धि हुई है और फिर विगत वर्ष की तुलना में पीओआई में इन आयातों में गिरावट आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से

आयात पीओआई में आधार वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। पुनश्च, संबद्ध देश से आयात, जांच की अवधि में कुल आयात, उत्पादन और खपत के संबंध में बहुत अधिक रहे हैं। कुल आयातों में चीन से होने वाले आयातों का हिस्सा क्षति अवधि में बहुत अधिक बढ़ा गया है। उपर्युक्त स्थिति पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में बनी रही। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद भी बहुत अधिक रही है और इसलिए यह पाटनरोधी शुल्क न रहने पर तो और भी अधिक बढ़ेगा।

ख. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

48. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर उसके कीमत प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों से उतराई मूल्य से की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों के उतराई मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई है। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए रिबेट, करों, डिस्काउंट और कमीशन का समायोजन किया गया है। क्षति का आकलन करने के लिए कीमत अधोविक्रयण एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अतः, प्राधिकारी ने एक गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया है और उसकी तुलना मौजूदा कीमत अधोविक्रयण का निर्धारण करने के लिए उतराई मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन पीओआई के दौरान इस विचाराधीन उत्पादन के लिए उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है। स्थिति निम्नवत है :

(क) कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण

49. कीमत अधोरदन/कीमत अधोविक्रयण प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

कीमत अधोरदन

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
ग्रीग (ग्रीग) फेब्रिक					
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
आयातों का उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रेंज	15-25%	5-15%	10-20%	10-20%
डिप्ड फेब्रिक					
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
आयातों का उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रेंज %	15-25%	10-20%	10-20%	10-20%
कुल					
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
आयातों का उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
कीमत अधोरदन	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रेंज %	15-25%	5-15%	10-20%	10-20%

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है या क्या इन आयातों का प्रभाव अन्य उन कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन करेंगे।

कीमत अधोविक्रयण

विवरण	मापन की इकाई	ग्रीग	डिण्ड	भारित औसत
आयात मात्रा	एमटी	15,855	13,606	29,461
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***
उतराई मूल्य	रुपए/किलोग्राम	***	***	***
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/किलोग्राम	***	***	***
कीमत अधोविक्रयण	%	***	***	***
कीमत अधोविक्रयण	रेंज %	5-15%	5-15%	5-15%

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना में बहुत कम होगा और एतद् द्वारा उसका भारी कीमत अधोविक्रयण प्रभाव होगा।

ख) कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन

52. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन प्रभाव का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण की प्रवृत्ति और बिक्री लागत की तुलना में आयातों के उतराई कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम बनी रही। अतः, यह पाटनरोधी शुल्क का समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर भारी निग्रहण/ अवमंदन प्रभाव को दर्शाता है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	115	115
बिक्री कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	113	113
आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	126	119	120

ग. घरेलू उद्योग पर आर्थिक पैरामीटरों का प्रभाव

53. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-2 यह अपेक्षा करता है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुनः यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है।

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

54. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा निम्नवत है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
क्षमता (ग्रीग और डिण्ड)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	121	121
सकल उत्पादन (ग्रीग और डिण्ड)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	124	126
क्षमता उपयोग (ग्रीग और डिण्ड)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	94	103	104
विचाराधीन उत्पाद का सकल उत्पादन (ग्रीग और डिण्ड)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	122	126
निवल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	104	104
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	106	106
मांग	एमटी	1,34,844	1,36,054	1,43,676	1,40,203

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार किया था। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और उसकी बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2011-12 में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

(ख) लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

56. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	115	115
बिक्री कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	113	113
लाभ/हानि	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	81	97	102
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	83	103	107
कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	111	108
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	86	105	107
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	82	96	91

57. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2011-12 में गिरावट हुई, फिर वर्ष 2012-13 में उसमें वृद्धि हुई और पीओआई में उसमें पुनः सुधार हुआ है।
- घरेलू उद्योग का लाभ, दर पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ ने भी लाभप्रदता के समान ही प्रवृत्ति का अनुपालन किया है। घरेलू उद्योग के निवेश पर प्रतिलाभ में विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- यह नोट किया जाता है कि इस अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता स्थिर बनी रही। इस अवधि में लाभ, दर पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ स्थिर बना रहा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कीमत पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग का स्थिर निष्पादन प्रभावी पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव है।

(ग) बाजार हिस्सा

58. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा समान ही बना रहा; वहीं क्षति अवधि में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने से संबद्ध देश के उत्पादक घरेलू बाजार को और अधिक हस्तगत करने से वंचित रह गए और इसलिए घरेलू उद्योग मांग में बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रह सकी है। उन्होंने पुनः यह दावा किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश एक बार फिर घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर अपना कब्जा कर लेगा और तद्वारा घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

(घ) रोजगार और वेतन

59. घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और वेतन की स्थिति निम्नवत है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	101	101
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	111	120

60. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2012-13 में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई और फिर पीओआई में इसमें मामूली सी गिरावट आई। क्षति अवधि में वेतन एवं पारिश्रमिक में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि वेतन एवं पारिश्रमिक में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ड) उत्पादकता

61. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की स्थिति अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	206	226
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	122	126

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता प्रति कर्मचारी और उत्पादकता प्रतिदिन संपूर्ण अवधि में उत्पादन के समान ही समान स्तर पर बने रहे।

(च) मालसूची

63. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
स्टॉक (मात्रा) औसत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	121	89
बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची	दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	122	114	84

64. उपर्युक्त तालिका में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई और फिर उसमें गिरावट आई। तथापि, मालसूची पीओआई में बहुत अधिक बनी रही।

(छ) पाटन की मात्रा

65. पाटन की मात्रा, जो इस बात का संकेतक है कि पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति पहुंचाई जा सकती है, दर्शाती है कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं बल्कि बहुत अधिक है।

(ज) पूंजी उगाहने की क्षमता

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन की स्थिति में पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता संगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के संघटक बहु-उत्पाद कंपनियां हैं।

(झ) वृद्धि

67. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में स्थिति निम्नवत है :

विकास प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	5.45	17.87	1.55
बिक्री मात्रा	%	-	2.99	2.88	(0.36)
बिक्री लाभ	%	-	18.06	(2.76)	0.13
बिक्री कीमत	%	-	13.97	(0.95)	0.54
लाभ प्रति इकाई	%	-	(19.32)	20.50	4.48
निवेश पर अर्जन	%	-	-3.86%	3.00%	-1.05%

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन मात्रा और कीमत पैरामीटर दोनों रूपों में सकारात्मक रहा है। घरेलू बिक्री मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा तथा लाभप्रदता में सुधार प्रदर्शित हुआ है जैसाकि लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों से देखा जा सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन से आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की वृद्धि में वास्तविक रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ञ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

69. संबद्ध देश से आयात कीमत, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं; की जांच यह दर्शाती है कि देश से आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम जिसके कारण भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन कारित हो रहा है। भारतीय उद्योग की कीमतों के लिए बेंचमार्क इस उत्पाद का पाटन करने वाले संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयात कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। संबद्ध वस्तु की मांग जांच की अवधि में भारी वृद्धि प्रदर्शित कर रही थी और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अतः, घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का उत्पाद है।

(ट) क्षति संबंधी निष्कर्ष

70. रिकार्ड में उपलब्ध विभिन्न सूचना के आधार पर तथा विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि चीन से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने समग्र रूप से वृद्धि प्रदर्शित की है और भारत में इसके उत्पादन एवं खपत की तुलना में इसकी मात्रा बहुत अधिक रही है। विभिन्न स्रोतों से आयात की तुलना में चीन से होने वाले आयातों का हिस्सा बढ़ा है। इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में अधोरदन होने की संभावना है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव पड़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग का निष्पादन विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में सुधरा है और स्थिर बना रहा। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सुधार हुआ है। क्षमता उपयोग लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, और नकदी प्रवाह में मामूली सा परिवर्तन हुआ है और यह घरेलू उद्योग की स्थिर स्थिति को दर्शाता है। यद्यपि, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर प्रतिलाभ प्राधिकारी द्वारा विचारित 22 प्रतिशत के स्तर से कम है, फिर भी घरेलू उद्योग निवेश पर सकारात्मक प्रतिलाभ अर्जित कर रहा है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग के सतत पाटन के कारण सतत क्षति नहीं हुई है।

(घ) अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

71. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है या नहीं, यह निम्नवत है :

(क) उन आयातों की मात्रा एवं कीमत जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई :

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू चीन जन.गण. से देश में आ रहे पाटित आयातों से क्षति हो रही है। अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात या तो न्यूनतम हैं या उनकी निर्यात कीमत बहुत अधिक है।

(ख) मांग में संकुचन और/या खपत की प्रणाली में परिवर्तन

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान, जांच की अवधि के दौरान हल्की सी गिरावट के बाद, वृद्धि हुई। तथापि, इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। अतः, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस उत्पाद की खपत की प्रणाली में परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(ग) घरेलू एवं विदेशी उत्पादों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के बीच, इसके सिवाय कि एक स्पष्ट बाजार अर्थव्यवस्था है, कोई बोधगम्य प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु के लिए केवल एक ही बाजार है जहां संबद्ध देश के पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित संबद्ध वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु दोनों समान वस्तुएं हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोग/अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद या उसके विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(ङ.) निर्यात निष्पादन

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में इस उत्पाद का थोड़ी मात्रा में निर्यात किया है। अतः, नगण्य निर्यात यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उपगत दावा केवल घरेलू बिक्री के संबंध में है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के अनुसार ही उतार-चढ़ाव आया है। अतः उत्पादकता में गिरावट क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

(छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन, क्षति का एक संभावित कारण नहीं हो पाया गया है क्योंकि इस जांच में समान वस्तु के संबंध में सभी पैरामीटरों की जांच की गई है।

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से निर्धारित क्षति कारित नहीं की गई है, तथापि निम्नलिखित पैरामीटर्स यह दर्शाते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा ही कारित की जाएगी।

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमत पर होना जारी रहे।
- ख. पाटन मार्जिन, कीमत अधोरदन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।
- ग. आयात पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन करेंगे। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है बल्कि, यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत एवं गैर-क्षतिकारी कीमत से भी कम है।
- घ. चीन से आयात पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद इस स्रोत से पाटित आयातों की भारी मात्रा आती रही। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और अधिक तीव्र हो जाएगा तथा उससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने लगेगी।

(ज) क्षति संबंधी निष्कर्ष एवं कारणात्मकता

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं स्पष्ट खपत के संगत रूप में इस तथ्य के बावजूद वृद्धि हुई है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। लाभ से संबंधित प्राचलों ने भी सुधार प्रदर्शित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में लाभ के रूप में क्षति नहीं हुई है तथापि, जांच की अवधि में चीन से आयातों की मात्रा इतनी अधिक रही जो यदि घरेलू उद्योग को चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों की उतराई कीमत से मिलान करने वाली कीमत को लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है। पाटन मार्जिन, कीमत अधोरदन

और क्षति मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है। तथापि, भारी पाटन मार्जिन के बावजूद यह समीक्षा निर्णायक समीक्षा होने के कारण प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पीओआई में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करना अपेक्षित है।

झ. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना

झ.1. निर्यातकों/विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

81. निर्यातकों/विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- (i) धारा 9क(5) का प्रथम परंतुक यह निर्धारित करता है कि शुल्क का विस्तार पाटन एवं क्षति दोनों की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना पर निर्भर है। पाटन अथवा क्षति की संभावना पर अलग से शुल्क में और अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है।
- (ii) चीन के उत्पादकों की उत्पादन क्षमता संबंधी सूचना भारत में संबद्ध वस्तु की आपूर्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का ब्यौरा प्रदान करती है।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

82. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- (i) चीन से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है। यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो संबद्ध देश से पाटन और भी अधिक तीव्र हो जाने की संभावना है।
- (ii) चीन से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। इसलिए, यह उत्पादक, पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में अपने उत्पाद की भारतीय बाजार में बिक्री और भी अधिक आक्रामक ढंग से करना शुरू कर देंगे।
- (iii) संबद्ध देश के निर्यातकों की क्षमता भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है।
- (iv) जुन्मा टायर कार्ड कंपनी लिमिटेड जो पीआरसी में नायलान 6 टायर कार्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह कंपनी कई विपरीत कारकों के बावजूद अपनी बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम थी क्योंकि वे बिक्री बढ़ाने और घरेलू क्षति के दूर करने के लिए सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात बाजार में बिक्री कर रहे थे। यही कार्यनीति संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के अन्य निर्यातकों द्वारा भी अपनाई जा रही है। चीन के उत्पादक अपनी घरेलू बिक्री में आई गिरावट को पूरा करने के लिए निर्यात बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
- (v) चीन में कुछ उत्पादकों की ज्ञात उपलब्ध क्षमता लगभग 3.69 लाख टन प्रति वर्ष और भारतीय मांग लाभ 1.4 लाख टन प्रति वर्ष पर विचार करते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाटन और भी अधिक तीव्र हो जाएगा।
- (vi) चीन द्वारा संपूर्ण विश्व को किए गए आयातों के आंकड़े यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि उनका संबद्ध वस्तु के लिए भारत एक सर्वाधिक बड़ा निर्यात बाजार है।
- (vii) इस संबद्ध वस्तु के लिए भारत एक आकर्षक बाजार है क्योंकि चीन से भारत को निर्यात कीमतें अन्य देशों को निर्यात कीमतों की तुलना में सदैव कम रही है।
- (viii) जांच की वर्तमान अवधि में पाटन आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है और पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है। इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन की निरंतरता बने रहने और वस्तुतः उसमें और भी अधिक तीव्रता आने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी होने पर भी भारी चालू पाटन मार्जिन पाटन की संभावना का भारी संकेतक है।
- (ix) संबद्ध देश से पाटन आयात बहुत अधिक बने हुए हैं और बाजार हिस्से पर उनका भारी वर्चस्व बने रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, चीन से उतराई कीमत पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारतीय कीमतों का अधोदहन करेंगी। अतः, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से भारी कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव होगा।
- (x) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्तागण अपने अधिप्रापण का निर्धारण कीमतों पर विचार करके करते हैं। ऐसा मामला होने पर बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता का घरेलू उद्योग पर विपरीत कीमत प्रभाव पड़ेगा।
- (xi) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बिक्री करने का चयन करता है तो घरेलू उद्योग पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

83. वर्तमान निर्णायक समीक्षा चीन जन.गण. से आयातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण करना अधिदेशित है। इसमें यह विचार करना भी अपेक्षित होता है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का प्रशमन करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। इस मामले में, चूंकि सतत पाटित आयात हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी से यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से इस उत्पाद का सतत पाटन होने की संभावना है। संबद्ध देश के उत्पादक और निर्यातक संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटित कीमतों पर कर रहे हैं। विगत जांच में भी पाटन मार्जिन बहुत अधिक था। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं रहता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन में वृद्धि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विगत एवं वर्तमान दोनों ही जांचों में पाटन मार्जिन बहुत अधिक था और यह कि जहां तक संबद्ध वस्तु की मांग और कीमत का संबंध है भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी का यह विश्वास है कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन में और भी अधिक वृद्धि होगी। यह एक तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद, संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन कर रहा है। निम्नलिखित विश्लेषण यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और भी अधिक बढ़ जाएगा तथा क्षति तीव्र हो जाएगी।

मौजूदा एवं पिछला पाटन मार्जिन स्तर

84. प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और अब आकलित पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्यात पाटित कीमतों पर होना जारी रहे और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उनके जारी रहने की संभावना है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा संपूर्ण क्षति अवधि में बहुत अधिक बनी रहीं। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से आयातों की यह मात्रा और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

85. वह कीमतें जिन पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है उन कीमतों से न्यूनतर हैं जिन पर घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री की जा रही थी। इसलिए, शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने के मामले में निर्यातकगण अपने आउटपुट का भारतीय बाजार में और अधिक सरलीकरण करेंगे क्योंकि उनके पास भारी क्षमता पहले से ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा यथादावाकृत इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बढ़ जाएगी।

संबद्ध देश में भारी क्षमताएं

86. चीन में मौजूदा क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाना कराये गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उनकी क्षमता भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादक संबद्ध वस्तु का पाटन और भी तेजी से करना प्रारंभ कर देंगे।

विदेशी उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

87. उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं। उच्च मांग और भारत में संबद्ध वस्तु के लिए अनुकूल बाजार परिस्थिति और चीन में उच्च उत्पादन क्षमता तथा चीन के उत्पादकों की निर्यात उन्मुखता को देखते हुए प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु की भारी मांग सृजित कर दी जाएगी।

पाटन एवं क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

88. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से आयातों के मौजूदा स्तर पर विचार करते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति और भी अधिक तीव्र हो जाने की संभावना है। पुनः, यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत घरेलू कीमतों का अधोदहन करेगी और उसका घरेलू कीमतों पर पर्याप्त निग्रहण प्रभाव भी होगा।

क्षति मार्जिन एवं पाटन मार्जिन की मात्रा

89. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई और मासिक विश्लेषण पर आधारित प्रस्तावित क्षति मार्जिन निम्नलिखित है :

विवरण	मैसर्स जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	असहयोगकर्ता निर्यातक
घरेलू उद्योग की एनआईपी का भारित औसत	***	***
उतराई मूल्य	***	***
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***
क्षति मार्जिन रेंज%	10-20	25-35

90. यह नोट किया जाता है कि यथानिर्धारित प्रस्तावित क्षति मार्जिन बहुत अधिक माना गया है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

- जुम्ना टायर कार्ड कंपनी लिमिटेड, चीन
- निंगबो नायलान कंपनी लिमिटेड, चीन
- हुआइआन नायलान कैमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन
- निंगबो जिन्लुन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन
- आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति का है और उनका प्रकटन विवरण में पहले से ही समाधान कर दिया गया है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात दायर किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है :

- (i) प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां करने के लिए प्रदान किया गया केवल तीन दिनों का समय पर्याप्त नहीं है।
- (ii) ऊपर उल्लिखित निर्यातकों द्वारा दायर विस्तृत प्रश्नावली प्रत्युत्तर को उनके द्वारा प्राधिकारी के समक्ष समय विस्तार की मांग करते हुए दायर किया गया प्रत्युत्तर, उनके अनुरोध के बावजूद भी रिकार्ड में नहीं लिया गया और उसे नामंजूर कर दिया गया।
- (iii) घरेलू उद्योग हमेशा संबद्ध वस्तु की अपनी बिक्री कीमत की मिलान आयातों के उतराई मूल्य से करता है; और चूंकि उतराई मूल्य में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क भी शामिल रहता है, इसलिए अभिगृहीतीय रूप से बिक्री कीमत हमेशा ही लगभग समान स्तर पर रहेगी। अतः, पाटनरोधी शुल्क प्रभावी हुए बिना, हमेशा ही कीमत अधोरदन का मामला बनता रहेगा।
- (iv) प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने से असफल रहे हैं कि इनमें से भारी आयात विदेश व्यापार नीति की शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत हुए हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क अपरिणामी रहती है।
- (v) एक एसएसआर मामले में, प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का सुनिश्चयन करना होता है। इसलिए, उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए जो प्रभावी शुल्क की समाप्ति की तारीख से यथासंभव निकटतम हों।
- (vi) पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य के वृष्टिपूर्ण आकलन पर आधारित है क्योंकि उपर्युक्त निर्यातकों ने एमईटी दर्जे का दावा किया है और उसकी जांच करने पर यह पाया गया कि उनके मामले में सामान्य मूल्य बहुत कम है।
- (vii) आवेदक द्वारा अत्यधिक एवं अनधिपन्नित गोपनीयता का दावा किया गया है।
- (viii) घरेलू उद्योग के पास एनटीसीएफ की पर्याप्त डिपिंग सुविधा नहीं है और इसलिए उपयोक्ता उद्योग को विदेशी स्रोतों से संबद्ध वस्तु का आयात करने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं रह जाता है।
- (ix) पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पीओआई के दौरान चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों में कमी आई है और चीन के निर्यातक अब अपना ध्यान भारत पर केंद्रित नहीं करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन के निर्यातकों ने अब अपना ध्यान अन्य बाजारों पर केंद्रित करना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट है कि चीन का क्षमता संवर्धन भारतीय बाजारों के बजाय तृतीय देश की बाजारों के प्रति प्रतिबद्ध है।

- (x) प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई है। इसलिए, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि घरेलू उद्योग को अब क्षति नहीं हो रही है।
- (xi) प्राधिकारी का यह निष्कर्ष निराधार है कि मौजूदा क्षति में कमी और घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी सुधार पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारा हुआ है।
- (xii) घरेलू उद्योग निरंतर क्षति का सामना नहीं कर रहा है। चीन के आयातों की कीमत में वृद्धि और मात्रा में कमी हुई है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है, लाभ निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह आदि में वृद्धि हुई है।
- (xiii) क्षतिकारी पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को प्रदर्शित करने वाले साक्ष्य का अभाव है।
- (xiv) निर्यात पर घरेलू उद्योग का फोकस घरेलू बिक्रियों में स्थिर बाजार हिस्से के लिए उत्तरदायी है।
- (xv) घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए तुलना विगतवर्ती अवधि अथवा आधार वर्ष से की गई है।
- (xvi) कूड एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में काफी गिरावट आई है यह 130 यूएस डालर से घटकर 40 यूएस डालर हो गई है। अपनाई गई पीओआई को पाटनरोधी शुल्क के विरुद्ध बैरोमीटर के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा संबद्ध वस्तु की कीमतों में समय-समय पर उतार-चढ़ावों के लिए पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण यथा मूल्य आधार पर किया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणी

92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति का है और उनका प्रकटन विवरण में पहले से ही समाधान कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात दायर किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है :

- (i) प्राधिकारी ने चीन में सभी निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाला ठीक ही माना है।
- (ii) सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन का संरचित लागत पर विचार करते हुए किया गया है जबकि घरेलू उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश (थाईलैंड) में लागत और कीमत के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान कराई है। याचिकाकर्ता यह दोहराते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण "किसी अन्य सूचना" के आधार पर नहीं किया जा सकता है जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में लागत और कीमत की सूचना उपलब्ध हो।
- (iii) जांच में भारी पाटन की मौजूदगी सिद्ध हुई है।
- (iv) संबद्ध देश से समग्र रूप में इस उत्पाद के भारी आयात हुए हैं, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने की संभावना सिद्ध होती है।
- (v) उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारी कीमत अधोरदन पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी निग्रहण प्रभाव पड़ेगा।
- (vi) चालू पीओआई में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक एवं बहुत अधिक है।
- (vii) आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तविक रूप से कम है। इसलिए घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमतों में कमी करने या बिक्री का अवसर खो देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोनों ही हालातों में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना रहेगी।
- (viii) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहेगी।
- (ix) गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।
- (x) पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है। शुल्क की सिफारिश यूएस डालर में निर्धारित राशि के आधार पर की जानी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अधिकांश विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्ति प्रवृत्ति के हैं और उनका प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है और उनका इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत शीर्षकों के अंतर्गत समाधान कर दिया गया है। ऐसा होते हुए भी, प्राधिकारी ने इन मुद्दों का समाधान संगत समझी गई सीमा तक समाधान निम्नवत कर दिया गया है :

- (i) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समय अपर्याप्त है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने न केवल विस्तृत टिप्पणियां दायर की हैं बल्कि यह पुनरावृत्तिक भी हैं। इसके अतिरिक्त, नियमों के अंतर्गत प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है।
- (ii) उपर्युक्त निर्यातकों ने अपनी निजी सहमति से प्रश्नावली प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा के पश्चात दायर किए हैं। इसलिए यह प्राधिकारी के रिकार्ड में नहीं है। इसलिए प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार पत्र का प्रश्न नहीं है।
- (iii) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी रहते बिना, हमेशा ही कीमत अधोरदन का मामला बनेगा, यह नोट किया जाता है कि वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है, उस कीमत से कम है जिस पर घरेलू बाजार में उस वस्तु की बिक्री की जा रही है।
- (iv) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयात शुल्क मुक्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए आयातों की मात्रा संभावना का निर्धारण करने के लिए असंगत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वह कीमत जिसपर पीओआई के दौरान शुल्क मुक्त आयात किए गए हैं और पीओआई के दौरान आयातों की मात्रा स्पष्टतः यह दर्शाती है कि वह कीमत क्या होगी जिसपर, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने की स्थिति में आयात होने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी इस तथ्य पर निरंतर विचार करते रहे हैं कि शुल्क मुक्त श्रेणी के अंतर्गत किए गए आयातों का आशय यह है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं होगी।
- (v) जहाँ तक निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाली अवधि के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले में विचार की गई पीओआई उपयुक्त है। यह एक सांविधिक अपेक्षा है कि एसएसआर कार्रवाई में पीओआई पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख से यथासंभव निकट की अवधि में समाप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा विगत में की गई कई निर्णायक समीक्षा जांचों में 6 माह की पोस्ट-पीओआई अवधि को भी अपनाया गया है।
- (vi) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य की वृष्टिपूर्ण कल्पना पर आधारित है, क्योंकि उपरोक्त निर्यातकों ने एमईटी दर्जे का दावा किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनकी निर्यातक प्रश्नावली विलंब से दायर किए जाने के कारण, अस्वीकार कर दी गई है।
- (vii) जहाँ तक याचिका में सूचना की गोपनीयता का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जहाँ कहीं अधिपत्रित हुआ वहाँ गोपनीयता प्रदान कर दी और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन कर दिया गया।
- (viii) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के पास एनटीसीएफ की डिपिंग करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त डिपिंग सुविधा है परंतु वह संबद्ध देश में डिप किए गए एनटीसीएफ की पाटित कीमतों के साथ डिप किए गए एनटीसीएफ की कीमतों के साथ मुकाबला करने में समर्थ नहीं हैं।
- (ix) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में भारी पाटन एवं क्षति के साक्ष्य पहले से ही उपलब्ध हैं जो पाटन एवं क्षति की संभावना के विश्लेषण की जांच करना महत्वहीन कर देते हैं। वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है वास्तव में उन कीमतों से कम है जिस पर घरेलू बाजार में उस वस्तु की बिक्री की जा रही है। इसलिए, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के मामले में निर्यातकगण अपने उत्पादन का भारतीय बाजार में सरणीकरण कर देंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही भारी क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा चीन में मौजूदा क्षमता के संबंध में प्रदान कराया गया साक्ष्य यह संकेत करता है कि यह संबद्ध वस्तु की भारत में मांग की तुलना में बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण करने की स्थिति में चीन के उत्पादक संबद्ध वस्तु का पाटन और अधिक तीव्र कर देंगे। उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं। भारत में इस संबद्ध वस्तु के लिए उच्च मांग और अनुकूल बाजार परिस्थितियों के और चीन के उत्पादकों की उच्च उत्पादन क्षमता तथा उनकी निर्यात उन्मुखता को देखते हुए इस बात की भारी संभावना है कि भारत में संबद्ध वस्तु की पर्याप्त मांग को चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पूरा किया जाएगा। पुनः यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत घरेलू कीमत का अधोरदन करेगी और उसका घरेलू कीमतों पर भी भारी निग्रहण प्रभाव होगा।
- (x) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि यह एक सुस्थापित तथ्य है कि इस समय घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप में पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के तथ्य के बावजूद बहुत अधिक रहा है। हालांकि पीओआई में घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं सहन करनी पड़ी, फिर भी आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी मात्रा में अधोरदन कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक सकारात्मक है।
- (xi) जहाँ तक चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए थाइलैंड पर विचार करने के घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने थाइलैंड को चीन संबद्ध देश के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था

वाले देश के रूप में थाईलैंड का चयन करने के लिए पर्याप्त कारण/सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी का यह विचार है कि चीन में समग्र आर्थिक विकास से अधिक उच्चतर स्तर और इस उत्पाद के उत्पादन के संबंध में उसकी उत्पादन लागत, चीन में क्षमता और निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए चीन और थाईलैंड को तुलनीय के रूप में मानना उपयुक्त नहीं होगा।

- (xii) जहां तक गैर-क्षतिकारी कीमत के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी ने गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित दिशानिर्देश के अनुरूप की है।
- (xiii) जहां तक शुल्क को यूएस डालर में निर्धारित राशि में सिफारिश करने का मुद्दा है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि प्राधिकारी द्वारा शुल्क के प्ररूप का निर्धारण अलग-अलग मामले की प्रकृति, परिस्थितियों और गुणावगुण को ध्यान में रखकर किया है और तदनुसार ही इस मामले में शुल्क की मुद्रा का निर्धारण किया गया है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में क्षति कारित हुई है।
- (xiv) यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग मुख्यतया घरेलू बाजार में प्रचालन करता है और घरेलू उद्योग की कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में निर्यात बिक्री नगण्य है।
- (xv) प्राधिकारी ने विश्लेषण एवं जांच की विगत प्रक्रिया का अनुपालन किया है। क्षति के सभी पैरामीटरों की जांच संपूर्ण जांच अवधि के संदर्भ में की गई है।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

94. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटनर प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग में और अधिक गिरावट आने से बचाएगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा, उपभोक्ताओं को इस वस्तु की होने वाली उपलब्धता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उपभोक्तागण अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

95. सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य उस पाटन का उपशमन करना होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है और भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति पुनर्स्थापित करना है जो देश के सामान्य हित में हो। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

96. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों और प्रदान कराई गई सूचना और इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और पाटन एवं परिणामी क्षति की निरंतरता की स्थिति और पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं :

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन हुआ है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और बहुत अधिक है।
- ख. यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन और भी अधिक तीव्र होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

सिफारिश

97. यथोपरि निष्कर्ष निकालने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क को अधोलिखित तालिका में यथाविनिर्धारित रूप से बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

98. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियमा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष/उप शीर्षक	ग्रेड	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	0.52	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	कोई अन्य	1.10	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण	चीन जन.गण	कोई अन्य	जियांग्सु हायांग कैमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड	1.10	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
4	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण	चीन जन.गण	क्र.सं. 1,2,3 को छोड़कर कोई अन्य		1.10	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
5	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण	चीन जन.गण को छोड़कर कोई अन्य	कोई भी	कोई भी	1.10	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
6	5902.10	सभी ग्रेड	नायलान टायर कार्ड फेब्रिक	चीन जन.गण को छोड़कर कोई अन्य	चीन जन.गण	कोई भी	कोई भी	1.10	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

अगली कार्रवाई

99. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य वहीं होगा जो सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित कर निर्धार्य मूल्य है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों के सिवाय अन्य सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

100. केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2015

(FINAL FINDINGS)

Subject: Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) originating in or exported from China PR.

No.15/32/2013-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules):

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. WHEREAS the Designated Authority (hereinafter also referred so to the Authority) had initiated an investigation concerning imports of “Nylon Tyre Cord Fabric” (hereinafter also referred so to as NTCF or the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) vide Notification No. 14/20/2003-DGAD dated 29.10.2003. On the basis of the recommendations made by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/20/2003-DGAD dated 9th March, 2005, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 36/2005-Customs dated 27.04.2005 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. WHEREAS, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority in respect of the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No 14/20/2008-DGAD dated 16th September, 2008. The Authority vide Final Findings Notification No. 14/20/2008-DGAD dated 31st March, 2009 concluded that the expiry of anti dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury and recommended continued imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the Central Government vide its Notification No. 41/2009-Customs dated 29th April, 2009 imposed anti-dumping on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
4. WHEREAS, the Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi, on behalf of (hereinafter referred to as the petitioners or the applicants) two of its member companies, namely, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. has approached the Authority with a duly substantiated application in accordance with the Act and the Rules, contending likelihood of continuation/recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
5. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority again initiated sunset review investigation vide Notification No. 15/32/2013-DGAD dated 17th April, 2014 to review the need for continued imposition of the anti dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
6. The validity of the anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 28th April, 2015 vide Notification No 21/2014-Customs dated 16th May, 2014.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Rules.

- b. The Authority issued a public notice No 15/32/2013-DGAD dated 17th April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- c. The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the Rules.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject countries in accordance with the Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.
- e. Copies of the letter and the exporter's questionnaire sent to the exporters/producers in the subject country were also sent to the embassy of the subject country in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject country as also other exporters / producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limits.
- f. The Authority sent exporter's questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with the Rules:
 - i. Ningbo Nylon Co Limited
 - ii. Junma Tyre Cord Co Limited
 - iii. Qingdao Lianchuang Stock Company Ltd
 - iv. Qingzhou Heli Chemistry Fibre Co., Ltd.
 - v. Shandong Baorun (Holding) Co., Ltd.
 - vi. Yantai Guo Guo Handicraft Company
 - vii. Zhangjiagang Ruiqi Cord Fabric Co.,Ltd.
 - viii. Shandong Anda Synthetic Fiber Products Co., Ltd.
 - ix. Weifang Great Dragon Chemical Fibre Co. Ltd./ Shandong Polytex
 - x. Jiangsu Qunfa Chemical Co. Ltd.
 - xi. Taizhou Chemical Fibres Company
 - xii. Shandong Hualian Group Co Ltd.
 - xiii. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co Ltd.
 - xiv. Wujiang Dingzhen Textile Co Ltd.
 - xv. Shandong Hualian Group Co Ltd.
 - xvi. Weifang Senyu Trading Co Ltd.
 - xvii. Foshan City Shunde District Qifa Textile Co Ltd.
 - xviii. Jiangsu Steed
 - xix. Shandong Hesheng Chemical Weaving Co Ltd.
 - xx. Shandong Shouguang Ruihua Non-Woven Fabrics Co Ltd.
 - xxi. Achin Webbing & String (Shanghai) Co., Ltd.
 - xxii. Baling Petrochemicals
- g. Response to the exporter's questionnaire and submissions was received from M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd. only. However, M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd. did not file market economy treatment questionnaire. Further, submissions on initiation of sunset review investigations and present investigations have been made by M/s. Junma Tyre Cord Company Ltd., Ningbo Nylon Co. Ltd., Huaian Nylon Chemical Fibre Co. Ltd. and Ningbo Jinlun Import & Export Co. Ltd.
- h. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers and User Associations (whose names and addresses were made available to the Authority by the applicants) of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed limit in accordance with the Rule 6(4):
 - i. Balkrishna Industries Ltd., Mumbai

- ii. Apollo Tyres Ltd.,Gurugon
 - iii. Falcon Tyres Ltd., Mysore
 - iv. Birla Tyres, Kolkata
 - v. Goodyear India Ltd.,Ballabhgarh
 - vi. TVS Srichakra Ltd.,Madurai
 - vii. JK Tyres & Industries Ltd.,New Delhi
 - viii. CEAT Ltd.,Mumbai
 - ix. MRF Ltd., Chennai
 - x. Madura Industrial Textile Ltd, Mumbai
 - xi. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), New Delhi
- i. Apollo Tyres filed importers questionnaire response. Submissions were made by Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), Apollo Tyres and J K Tyre & Industries.
 - j. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was 1st October, 2012 to 30th September, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
 - k. The domestic industry had submitted the transaction wise data sourced from the secondary source IBIS, Mumbai. The Authority procured the same from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) as well for comparison. The Authority found that the import volume reported in the IBIS data was significantly higher (approximately 21%) than reported in the DGCIS data and, therefore, the Authority has relied upon the IBIS data for the injury analysis in present SSR investigation as has been done by the Authority in various previous investigations in such situations.
 - l. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
 - m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
 - n. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 21st January 2015. All the interested parties attending the hearing were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.
 - p. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the all the interested parties on 06.04.2015. The post Disclosure Statement submissions have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
 - q. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been examined and addressed in this disclosure statement.
 - r. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and other interested parties was carried out to the extent deemed necessary.
 - s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has carried out the investigation on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
 - u. *** in this Final Findings Notification represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - v. The exchange rate adopted for the POI is 1 US \$ =Rs 56.89.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**C.1 Submissions by the Domestic Industry**

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration:
- (i) The product under consideration is “Nylon Tyre Cord Fabric” or NTCF. NTCF is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animals driven vehicles etc.
 - (ii) Nylon Tyre Cord Fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Greige fabric" and also "dipped fabric". These are only different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is buying both Greige and dipped fabric. In addition, domestic industry is also manufacturing CTC grade of NTCF which is used by the cycle tyre manufacturers.
 - (iii) All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, and further under custom subheading no. 5902.10 of the Customs Tariff Act.
 - (iv) There is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from the subject country. The Authority has come to the same conclusion in the final findings of the original investigation and the subsequent sunset review investigation. In view of the same, petitioners submit that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in accordance with the Rules.

C.2 Submissions made by the producers/exporters/other opposing interested parties

10. None of the other interested parties has raised any issues with respect to the product under consideration and like article.

C.3 Examination by the Authority

11. The product under consideration in the present review investigation is Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) originating in or exported from China PR. NTCF is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animals driven vehicles etc. Nylon Tyre Cord fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Greige fabric" and also "dipped fabric". These are only different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is buying both Greige and dipped fabric. The product under consideration remains the same as it was in the original investigation and all previous sunset review investigation.
12. All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59 and further under customs subheading no. 5902.10.00 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and in no way binding upon the scope of the present investigation.

C.4 Like Article

13. The applicants submitted that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject country and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. None of the interested parties made any submission disputing the claim of the petitioners in this regard. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject country.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. The Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi, on behalf of two of its member companies, namely, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. has approached the Authority claiming to be the domestic industry under the rules.

D.1 Submissions made by the Domestic Industry

15. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:
- (i) The petition was filed by the Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI) (hereinafter referred to as ‘petitioner’) which represents domestic producers of the product under consideration in India. Two of its member companies, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. also referred to as “petitioner companies” or

- “petitioners” have provided relevant financial information to file the petition for the review, continuation and enhancement of anti dumping duty in force on imports of NTCF from the subject country. In addition to the petitioners, Madura Industrial Textiles Limited is also producing product under consideration in India.
- (ii) The petitioners command majority proportion in Indian production in the POI and, therefore, constitute domestic industry. Further, in case of sunset review, standing is not required to be examined.
 - (iii) One of the group companies of M/s Century Enka Limited, M/s Birla Tyres is regularly importing small quantities of duty free NTCF from China. The volume of imports made by M/s Birla Tyres are quite low considering gross imports of the product under consideration in India from China, production of M/s Century Enka Limited, Indian production and consumption of the product under consideration in India. Therefore, the Authority may kindly consider M/s Century Enka Limited as eligible domestic industry.
 - (iv) Both, Divisional Bench at Kolkata and Chennai High Courts have passed final orders clearly holding that the Designated Authority has sufficient discretion under Rule 2(b).
 - (v) In light of the facts stated above, the petitioners may be considered as eligible domestic industry.

D.2 Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

16. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing: -
 - (i) The petitioners in the current case cannot be treated as domestic industry for the reason that while one of the petitioners is importing the subject goods through its related company, the other petitioner has a related company in Thailand which is exporting the subject goods to India.
 - (ii) Since petitioners are related either to importers or exporters, they are not entitled to be treated as domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

17. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

18. The Authority notes that the application has been filed by the Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI) (referred to as ‘petitioner’) which represents domestic producers of the product under consideration in India. Two of its member companies, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. also referred to as “petitioner companies” or “petitioners” have provided relevant financial information to file the petition. The Authority further notes that apart from the applicant, M/s Madura Industrial Textiles Limited also manufactures the like article in India. However, no response has been received from M/s Madura Industrial Textiles Limited, either supporting or opposing the present investigation. It is noted from the information provided by the domestic industry that the share of production of the participating companies accounts for a major share in the total Indian production.
19. It has been brought to the attention of the Authority that M/s Birla Tyres, which is one of the group companies of M/s Century Enka Limited, is regularly importing small quantities of duty free NTCF from China. The domestic industry has claimed that the volume of imports made by M/s Birla Tyres are quite low considering gross imports of the product under consideration in India from China, production of M/s Century Enka Limited and Indian production & consumption of the product under consideration in India. While contending that Century Enka should not be treated as eligible domestic industry, it is noted that none of these interested parties has provided any information with regard to volume of imports by Birla Tyres. Birla Tyres has preferred not to cooperate with the Designated Authority in the present investigation. Even though ATMA has been participating in the present investigation and Birla Tyres is its member, ATMA has also not provided any information with regard to volume of imports by Birla Tyres. The Authority concludes that in this background, it would be appropriate to consider M/s Century Enka Limited as eligible domestic industry. It is seen that the production of M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. in the investigation period constitutes 94.56% of Indian production and, therefore, the applicants have been treated as domestic industry within the meaning of the Rules.
20. In view of the above position and having regard to the Anti-dumping Rules, the Authority determines that M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. account for a major proportion of total domestic production of the subject goods during the POI and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES**E.1 Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

21. The following miscellaneous submissions have been made by producers/ exporters/importers/other interested parties: -
- (i) Claims of domestic industry in non confidential petition are contradictory to the statement made by the Authority in the Initiation Notification. There is no claim of injury in the narrative version of the Petition, whereas the Authority has made observations that the domestic industry continues to suffer injury. Domestic industry has deliberately provided wrong and incomplete information for getting sunset review investigation initiated and later on supplemented the same with Proforma IV-A.
 - (ii) Domestic industry was in good health and was not suffering any injury at all. The investigation has been initiated on erroneous grounds and the entire process is liable to be vitiated.
 - (iii) The Applicants have raised no cogent points that the expiration of measure with regard to the subject country will result in recurrence of injury to the domestic industry. Further, any 'unbiased and objective' examination of the evidence provided in the Application would not justify the initiation of the investigation due to insufficiency of evidence.
 - (iv) The Applicants have simply filed the present application with a single-minded motive to seek the extension of the ADD without appropriately adducing evidence to substantiate their claims. However, the ADD cannot continue because India has taken an in-principle stand before the WTO agreeing not to extend the measure beyond a period of 10 years.
 - (v) If the DI genuinely feels harmed by the exports, it may file a fresh application for investigation, along with substantive evidence. In an original investigation the dumping and injury has to be established. However, in an SSR only the likelihood of injury is to be established.
 - (vi) The exporter reserves the right to file rejoinder submission if any issues are raised by the domestic industry with regard to Exporters Questionnaire responses filed by them.
 - (vii) The Applicants have forwarded their information in the prescribed pro-forma which is actually meant for the original application and not for an SSR.
 - (viii) The contention of the Applicants that initiation becomes mandatory, when a request for doing so is made, is wrong.
 - (ix) The POI adopted in the investigation is erroneous in view of the fact that the investigation should end as close to the date of initiation as practicable.
 - (x) The Applicants have not given satisfactory reasons for resorting to confidentiality in relation to substantial information in its NCV petition.
 - (xi) The claims of the Applicants that initiation of SSR is compulsory under certain provisions do not hold good. The Applicants have referred to certain judgments of the Delhi HC to support the argument. However, amendments have been made to the AD Rules subsequent to the judgments cited and hence, the initiation of a review is contingent on the fulfillment of the conditions pertaining to the existence of good and sufficient grounds.
 - (xii) The claims of the Applicants that there is no prescribed methodology for examining the likelihood of dumping and injury in a SSR stand rejected in light of the presence of relevant provisions underlining the said procedure.

E.2 Submissions by the domestic industry

22. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry: -
- (i) The exporter questionnaire itself is so grossly deficient that the domestic industry is not in a position to respond to the same.
 - (ii) Scope of original investigation and sunset review investigations are totally different. Fresh petition can be filed if dumping of a product is causing injury to the domestic industry. However, the scope of sunset review is whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry. Further, the interested parties themselves concede that in a sunset review, the Designated Authority is required to examine likelihood of injury. Despite so, the interested parties have contended that the Designated Authority has stated material injury in the Initiation Notification.
 - (iii) The duty free imports are also causing injury to the domestic industry and, therefore, there is no justification for excluding such volumes.
 - (iv) There is no prescribed format for filing sunset review petition. In the absence of the same, the petitioners have adopted the format for fresh application.

E.3 Examination by the Authority

23. The following is the examination of the Authority: -

- (i) The Authority has made the present determination on the basis of Anti Dumping Acts, Rules and the Practices being followed by the Designated Authority.
- (ii) It has been contended that the initiation notification is contrary to the petition filed by the domestic industry with regard to claim on injury. It is, however, to be noted that the Authority had initiated the investigations on the grounds of likelihood of injury to the domestic industry as is evident from the notice of initiation. The Authority notes that the notice of initiation is required to be read in its entirety and not in isolation.
- (iii) It has been contended that the domestic industry has not suffered injury and performance of the domestic industry has improved on account of a number of factors. The Authority, however, notes that the present investigation being a sunset review investigation, the Authority is required to consider both continuation and recurrence of dumping and injury to determine whether expiry of duty is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.
- (iv) As regards the argument that petitioner has not provided sufficient justification that expiry of duty shall lead to injury to the domestic industry, the Authority holds that the petition contained relevant material in this regard and the present determination is based on relevant evidence with regard to likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.
- (v) As regards the opinion expressed by Govt. of India before WTO for not continuing measures after a period of 10 years, the Authority notes that there is no decision by WTO nor any amendment to the Indian law providing that the anti dumping measures should not go beyond a period of 10 years if dumping is likely to continue or recur. The Indian Rules provide that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may from time to time extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension. Thus, if the investigation shows that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty, the anti dumping duty is required to be extended for a further period of five years.
- (vi) As regards the contention that domestic industry can file a fresh petition and the present duty should be allowed to expire, the Authority notes that the scope of fresh petition is entirely different from the scope of sunset review investigation. In a review investigation, the Authority is required to determine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, whereas, in a fresh investigation the Authority is required to determine whether the product under consideration is being dumped in India, whether import of the said article causes or threatens material injury to an industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India and whether a causal link exists between the dumped imports and injury. Thus, scope of sunset review is entirely different from the scope of fresh investigation. In any case, the fact that domestic industry has a right to file a fresh petition does not bar the domestic industry from filing a petition seeking sunset review investigation.
- (vii) As regards the arguments that the petition was filed in a form and manner prescribed for original investigation, the Authority notes that the petition contained all relevant information with regard to likelihood of dumping and injury, in addition to all relevant information prescribed for a fresh case.
- (viii) As regards the contention that the claim of domestic industry with regard to mandatory nature of sunset review is wrong, the Authority notes that the present determination is based on positive evidence with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- (ix) As regards the contention that the POI adopted in the investigation is erroneous in view of the fact that the investigation should end as close to the date of initiation as practicable, the Authority notes that the investigation period considered is appropriate and reasonable considering the facts of the case. In any case, there is no evidence on record to show that consideration of subsequent period would have led to significantly different conclusion. The Authority also notes that there is no legal prescription that the investigation should end as close to the date of initiation as practicable.
- (x) As regards the confidentiality claims in the petition, the Authority notes that confidentiality has been allowed to the extent found relevant.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submissions by the domestic industry

24. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - a) China is a non-market economy country. No WTO member country has granted market economy country status to China after following detailed evaluation procedure and examination under the WTO Rules. None of the Chinese producers/exporters has claimed market economy status. In fact, only one exporter from China has filed questionnaire response and none of the other Chinese producers has even filed questionnaire response. The sole exporter from China who has filed questionnaire response, M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd., has also not claimed market economy status. Thus, in any case, question of considering grant of market

economy status does not arise. The rules provide that the Authority shall examine market economy status claim only if a duly substantiated claim is made by the Chinese producers.

- b) In the previous investigations also, the Designated Authority has not granted market economy status to M/s Ningbo Nylon Company Limited (Producer) and M/s Ningbo Jinlun Import & Export Co. Ltd. (related Exporter). Normal value is required to be considered in accordance with Rule 7. Further, the rules have laid down a particular hierarchy in this regard and the same must be followed for determination of normal value. The rules provide for consideration of cost or price of the product under consideration in market economy third country.
- c) Petitioners have identified Thailand as an appropriate market economy third country. Thailand is an appropriate surrogate country for China for the following reasons:
 - (i) There is more than one domestic producer in Thailand and, therefore, the market is competitive.
 - (ii) There are significant imports of the product in Thailand. It further establishes existence of significant competition in Thailand.
 - (iii) Complete availability of all relevant information is one of the major reasons for adopting Thailand as an appropriate surrogate country.
 - (iv) The product types involved are comparable.
 - (v) China has exported Greige and dipped fabric to India. Dipped fabric is produced from Greige fabric. Thai producers have produced Greige and dipped fabric in Thailand and, therefore, the product types are quite comparable. The petitioner has not resorted to weighted average comparison. The petitioner has resorted to comparison on a comparable basis by comparing Greige fabric price with Greige fabric cost and dipped fabric price with dipped fabric cost.
- d) Accordingly, the petitioners have determined ex-factory selling price of Greige and dipped fabric in Thailand which has been adopted by the petitioners for the purpose of determining normal value.
- e) The responding exporter, Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd., has claimed export price after reporting the expenses on account of ocean freight and marine insurance only from FOB price to India. The exporter may explain how they have exported the product without incurring the other expenses, which are routinely found in case of exports from China.
- f) The petitioners have determined separate dumping margin for Greige and dipped product owing to significant cost and price difference between the two. It would be seen that the dumping margin is significant and above de minimis levels.
- g) The producers/exporters from the subject country would resort to further dumping, should the present anti-dumping duties be revoked.

F.2 Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

- 25. Following are the submissions made by the exporters and other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - (i) Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd. has not applied for Market Economy Treatment. They would accept the normal value the Authority decides.
 - (ii) The imports from the subject country are subject to “duty free” measures and as such should have been excluded from the total volume of the subject goods for the purposes of undertaking any volume injury analysis. As the imports from China are under the duty exemption schemes and as such, cannot cause injury to the DI, taking such exports into consideration for the determination of dumping margin is not correct.
 - (iii) The determination of Normal Value by Applicants is erroneous.
 - (iv) Normal Value determined had been contrived upwards to claim the unfair benefits of imposition of ADD on imports. Further, Normal Value has not been disclosed and a range of USD 0-10 has been provided which is too wide for the purpose of any reasonable understanding.
 - (v) Normal Value has been determined considering Thai data. The Applicant has not provided reasons for the selection of Thailand as the appropriate market economy. There is simply no comparison between China and Thailand either on the basis of cost of production or on the basis of the prevailing domestic selling prices of NTCF that is meant for home consumption in the two countries. There is significant variation in the grades of the PUC as admitted by the Applicants also. Thus, any analysis that has been undertaken on a weighted average basis will be erroneous and inapplicable.
 - (vi) It has been further claimed that wage rate in Thailand is about 30-50% higher than in China and the scale of operation in China in relation to the subject goods is nearly 30 times that of Thailand. Thus, conversion cost in China is much lower.
 - (vii) Thai Baroda Industries Ltd. was a sick unit before it was acquired by SRF and would result in higher operation costs.
 - (viii) Certain costs from Taiwan producers have been used to determine the normal value for Greige fabric, and such a normal value cannot be considered as the prevailing price in Thailand.
 - (ix) It appears that producers in Thailand do not sell Greige fabric and it thus implies that Thailand is not at the same level of development in relation to the product in question as compared to China.

- (x) In each investigation, the Authority is required to determine the market economy status of each exporter afresh and it has nothing to do with the determination made in the previous investigation.
- (xi) M/s. Junma Tyre Cord Company Ltd., Ningbo Nylon Co. Ltd., Huaian Nylon Chemical Fibre Co. Ltd. and Ningbo Jinlun Import & Export Co. Ltd. have claimed market economy status in the Questionnaire response filed by them. These parties have further claimed that dumping margin should be calculated based on their claim of normal value and export price.
- (xii) Bulk of imports was made under the duty exemption schemes and would not attract anti dumping duty. All duty free transactions should be removed from the import data to arrive at 'export price'.

F.3 Examination by the Authority

26. As regards the submission that the domestic sales price of the respondent exporter should be considered for determining the normal value, the Authority holds that China being non market economy, the domestic price cannot be relied upon as being reflective of market price. Moreover, as per the evidence on record with the Authority, only Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd. has filed exporter's questionnaire response but without Market Economy Treatment Questionnaire. The respondent exporter from China has not claimed market economy treatment.
27. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by India and other WTO Members. Therefore, in terms of para 8(2) of the Annexure 1 of Anti-dumping Rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
28. As per Paragraph 8, Annexure I to the Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence, as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire, to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-
 - a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and ,
 - d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
29. The Authority notes that M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co., Ltd., China PR, is the only company from China PR which has filed exporter's questionnaire response in the present investigation. The company has not claimed market economy treatment by filing the required market economy questionnaire response. The Authority further notes that none of the other producers and exporters of the subject goods from the subject country has submitted the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by the respondent Chinese company, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
30. As far as the claim of the domestic industry to consider Thailand as the appropriate country to determine the Normal Value for China is considered, the Authority is of the view that the applicant domestic industry has not provided sufficient reasons/information for the selection of Thailand as the appropriate market economy country for China, the subject country. The Authority is of the view that considering the much higher level of overall economic development in China and production cost, capacity and export orientation in China with respect to the product concerned, it would not be appropriate to consider China and Thailand as comparable. The Authority, therefore, has adopted India as the appropriate country for construction of normal value for China.

F.4 Determination of Normal value

31. The Authority indicated in the initiation notification that the petitioner has claimed the constructed normal value in case of China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including adjustment on selling, general & administrative expenses and profit, in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. However, none of the interested parties, including the applicants and Chinese producers has placed any material fact before the Authority to select an appropriate market economy third country for the purpose. The domestic industry has

submitted that India should be treated as an appropriate surrogate country for China in this matter and the normal value should be determined accordingly. None of the opposing parties has disputed the claim of the domestic industry.

32. The Authority has determined the normal value in China PR on facts available basis, in terms of para 7 of Annexure 1 to the Anti-dumping 17 Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all exporters from China PR has been constructed by taking into account the international price of the major input viz. Caprolactam (CPL) Nylon-6 Chips, Yarn, Scarp and Auxiliary at the price at which domestic industry has sourced the other raw materials. Further, the consumption norms, conversion cost and SGA expenses of the domestic industry have been adopted. After adding a reasonable profit margin of 5%, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters of China PR, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

F.5 Determination of Export Price

M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd., China PR

33. The Authority notes that only M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd., China PR has responded in the form and manners prescribed and has furnished the requisite information to determine the net export price. The Authority made adjustments on account of handling charges, overseas transportation, international insurance, bank charges and VAT adjustment as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd., China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Non-cooperative exporters

34. As far as the non-cooperating exporters are concerned, it was noted that the volume of exports by cooperative exporter being approximately ***% of total imports from the subject country and thus not being representative of the total imports, the lowest import price based on the best available information has been taken into account for determining their dumping margin. Adjustments like ocean freight, bank charges, VAT etc. have been allowed for arriving at export price at ex-factory level. By adopting this method the export price at ex-factory level in respect of non-cooperating exporters for the subject goods has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

F.6 Dumping Margin

35. Comparing the normal value and export prices as determined in the preceding paragraphs, the dumping margin has been determined by the Authority as follows:

Particulars	M/s. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	Non-Cooperative exporters
Wt Avg. Normal Value- US\$/Kg	***	***
Export Price- US\$/Kg	***	***
Dumping Margin- US\$/Kg	***	***
Dumping Margin- %	***	***
Dumping Margin Range- %	10-20	35-45

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions by the Domestic Industry

36. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- Demand has shown an increasing trend over the injury period, except a slight decline in the POI.
- Imports of the subject goods from China PR has gradually increased in absolute terms from the base year till 2012-13 and then declined in the POI. However, imports in the POI were significantly higher than imports in the base year. Further, imports from the subject country have remained significant in relation to total imports, production and consumption in the POI.
- There would be significant price undercutting in the absence of anti dumping duty.

- d. Landed price of imports, in the absence of anti dumping duty, is substantially below the cost of production of the Domestic Industry. Both the landed price of imports and selling price of the domestic industry have increased and decreased in tandem. Further, imports with anti-dumping duty are neither suppressing nor depressing the prices of the domestic industry. With anti-dumping duty in place, the import prices are entering the Indian market at reasonably better prices. The anti dumping duty in force has prevented injury to the domestic industry.
- e. The production and sales of the domestic industry increased over the injury period. Capacity utilization of the domestic industry has, however, declined over the injury period.
- f. Market share of the domestic industry has remained in similar region whereas that of imports from the subject country increased over the injury period.
- g. The profitability declined in 2011-12, increased in 2012-13 and then declined in the POI. However, the profitability of the domestic industry has been stable over the period.
- h. Profit before interest, cash profits and return on investment of the domestic industry showed the same trend as profits. The stable performance of the Domestic Industry in respect of price parameters is reflective of the effects of anti dumping duty in force.
- i. Inventories with the domestic industry have increased till 2011-12 and then declined. However, the inventory has remained significant in the POI.
- j. The productivity of the domestic industry has moved in tandem with the production. In general, productivity has remained more or less constant over the injury period.
- k. Dumping margin calculated in respect of imports from China PR is significant.
- l. Imports without anti-dumping duty would undercut the domestic price and cessation of anti-dumping duty shall have significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- m. Performance of the Domestic Industry in terms of capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow, etc. has improved. The domestic industry has not suffered continued injury as a result of the present anti dumping duties which acted as a deterrent to the unfair trade practice of the subject country.
- n. India is the biggest export market for subject goods for Chinese exporters. Should the anti-dumping duty be revoked, the producers and exporters in the subject country would intensify dumping in India.
- o. The exports from China to third countries are at much higher prices as compared to Chinese exports to India. It clearly shows that the Chinese producers are able to sell in the Indian market at much lower prices. Due to anti-dumping duty in existence, these prices are not injuring the domestic industry. However, if the anti-dumping duty ceases, these prices would cause material injury to the domestic industry.
- p. Withdrawal of anti dumping duties shall only lead to intensified dumping since dumping has continued in huge volumes since the year 1999-00 despite anti-dumping duties being imposed.
- q. The import prices without anti-dumping duty are materially below the selling price of the domestic industry. The consumers would, therefore, switch to imported product in the event of cessation of anti dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- r. Should the demand for the domestic industry's product decline in the market, the domestic industry's sales will decline.
- s. Should sales for domestic industry decline, it would directly impact production and consequently capacity utilization. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to adversely impact market share, domestic sales, production and capacity utilization of the domestic industry.
- t. Should the domestic industry respond to the Chinese competition after cessation of anti dumping duty by reducing the prices, it shall imply significant adverse price effect on the domestic industry. Should the domestic industry sell at prices comparable to Chinese prices, the domestic industry will not be able to recover its cost of production and thus would suffer significant financial losses, negative cash flow and negative return on investment.
- u. Buyers decide their procurement on the basis of relative prices offered by the foreign producers and domestic industry. If the prices offered by the foreign producers are lower, the buyers would increase their off-take from foreign producers. In the present case, if anti dumping duties are removed, the exporters from subject country shall further capture the market for subject goods in India given high production capacities and low export prices.
- v. There is likelihood of intensified imports in case existing anti-dumping duty ceases.
- w. The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

- x. The anti dumping duties are required to be imposed in accordance with the dumping margin and injury margin.
- y. The domestic industry is also manufacturing CTC grade of NTCF which is used by the cycle tyre manufacturers. However, there is no import of this grade in the POI.
- z. The form of measure is required to be kept as fixed quantum.

G.2 **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

37. Following submissions have been made by other interested parties with regard to the injury and causal link: -

- a. None of the economic parameters shows that domestic industry has suffered material injury.
- b. The domestic industry has not provided any factual basis with reasoned and conclusive justification that there is likelihood of such continuation or recurrence of injury to the domestic industry if the existing duty ceases.
- c. The domestic industry has been earning good profits during the period of investigation and past three years. Earnings per share are abnormally high as is evident from the segment results of TTB segment of SRF and also annual reports of Century Enka.
- d. The domestic industry has not provided information for post period of investigation simply because its profitability has further improved beyond the period of investigation.
- e. The exporter has requested for the basis and data on which the Authority has relied upon to come to the conclusions about existing injury to the domestic industry.
- f. If the DI genuinely feels harmed by the exports, it may file a fresh application for investigation along with substantive evidence. In an original investigation, the dumping and injury has to be established. However, in an SSR only the likelihood of injury is to be established.
- g. There is a contradiction in the claims of the applicants. On one side, they claim that the DI's health has been fairly good and on the other hand they claim that the DI has not been able to realize a fair selling price.
- h. The application is full of contradictory claims. The decline in demand has been attributed to recession in the automobile industry at one place, whereas at another place, it has been said that the demand has not registered any negative growth at all.
- i. The decline in demand only signifies that the capacity expansion done by the DI miscalculated the anticipated rise in demand. The injury due to this cannot be attributed to imports.
- j. The price depression or suppression of the PUC if the duty is ceased is merely a conjecture by the applicants.
- k. The applicants have mentioned that China makes the maximum exports of the subject goods to India, India being a "lucrative market" for it to dispose off its goods. However, the claim of the applicants is not supplemented with any evidence or source. Further, the data provided by the applicants themselves clearly shows that the Chinese exporters have not been India-centric and hence claims made by the applicants in this regard are blatantly false.
- l. The presence of freely disposable present and potential capacities with the foreign producers does not provide details of their commitment to supply the subject goods so produced to India.
- m. The export price from China to India is below the export price to other countries because this is dependent on demand and supply situation in the concerned market.
- n. The injury, if any, to the DI is not due to dumping but other causes which are changes in patterns of consumption and the export inclination of the DI. The applicants have deliberately chosen not to provide information/data that was inconvenient to them.
- o. Another domestic producer, Madura Industrial Textile Ltd. has commenced production of NTCF in India recently and has installed capacity of about 20,000 MT. The injury herein is likely due to the internecine competition amongst the domestic producers.
- p. There is no continued injury being faced by the DI. The CIF price of the imports from the subject country has increased and the volume of the imports has decreased in the POI.
- q. An industry suffering injury, as claimed by the applicants, would not add to its capacity every year, as has been done by the applicants. In fact, the performance of the DI has improved consistently.
- r. The applicants have failed to provide any credible evidence to establish that the expiry of the duty would lead to recurrence of injurious dumping. The contention of the applicants that India is the biggest export market for Chinese exporters of the subject goods is not supplemented with a source to which the information can be traced back and affirmed.
- s. The application lacks positive evidence related to likelihood of dumping and alleged injury. There is no causal link between the two and the application is liable to be terminated due to these inconsistencies.
- t. There has been a significant fall in the prices of Crude & Petroleum products from US\$ 130 to US\$ 40. The POI adopted should not be considered as barometer for levying anti dumping duty, or the anti dumping duty must be levied on ad valorem basis to account for the fluctuations in the prices of the subject goods from time to time.
- u. The volume of imports from China has declined by 8% in the POI as compared to the previous year. This signifies that Chinese exporters have moved their focus to supplying to other markets. The source of China's export information has not been provided by the applicants.

- v. The plants of the applicants are more than 20 years old leading to higher cost and making their prices uncompetitive. The Authority must reject their claim of higher non-injurious price.
- w. The applicants' strong performance has resulted not from the existence of anti dumping duty but from the structural changes, de-bottlenecking operations and new investments made by them.
- x. Landed price from China increased by 20% in the POI as compared to the base year. Cessation of anti dumping duty would only further increase their selling price to India so as to increase their margins.
- y. No injury is likely to recur in view of the above.

G.3 Examination by the Authority

38. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on consequent injury to the domestic industry and analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. While issues concerning facts and figures and performance of domestic industry in respect of various economic parameters have been addressed ipso facto in the injury analysis, other submissions made by the interested parties have been examined and addressed below:
- a. It has been contended that the domestic industry has not suffered injury and the performance of the domestic industry has shown improvement in respect of a number of economic parameters. The domestic industry has contended that the present investigation is a sunset review and the Authority is required to determine likelihood of injury. The Authority notes that the Authority is required to first ascertain whether the domestic industry has suffered continued injury; and if not so, the Authority should examine likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. The present determination is based on the examination of injury to the domestic industry over the current period and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present anti dumping duty.
 - b. It has been contended that the domestic industry has not provided information with regard to post POI, the Authority considers that information with regard to post POI is relevant only in a situation where the domestic industry has not suffered injury in the current POI and the information for the POI does not show likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. In case the information for the POI shows dumping and injury to the domestic industry and/or its likelihood, the Authority is not required to consider the post POI data. In the present investigation, the Authority notes that the POI shows significant dumping and the injury margin is also significant as the landed value of imports from China is significantly lower than the NIP of the domestic industry and, therefore, the Authority is not required to consider the post POI data.
 - c. With regard to the arguments of interested parties concerning decline in demand for the product, the Authority has examined factual position at the relevant place in the present determination. Further, it is noted that the capacities with the domestic industry are lower than demand for the product in the country and, therefore, the facts of the case do not show that the domestic industry is likely to suffer injury due to decline in demand of the product in the country.
 - d. As regards the argument on the absence of evidence with regard to freely disposable present and potential capacities, the Authority notes that the determination is based on documentary evidence in this regard. Further, the Authority has seen the questionnaire response filed by the Chinese exporters in this regard. In any case, it is seen that the volume of imports from China during the POI was 29,461 MT and constituted 21.01% demand of the product in India. Thus, the current volume of imports itself is significant and sufficient enough to establish likelihood of injury in case of cessation of duty.
 - e. As regards the contention that China's export price to other countries are higher than those to India, the Authority notes that the prices at which goods are being exported to India itself are sufficient enough to establish likelihood of injury in the present case.
 - f. As regards the argument that injury to the domestic industry may be from other domestic producer, Madura Industrial Textile, the Authority notes that ATMA has participated in the present investigation as a user industry association and the petitioners have made sales to those companies as well who are member of ATMA. ATMA has not provided any evidence to show that selling price of Madura Industrial Textile is lower than import price from China. It is, thus, not established that injury to the domestic industry is likely from Madura Industrial Textile. Further, the Authority has not found that the domestic industry is suffering injury and, therefore, it is not a case where the claimed injury to the domestic industry may be from Madura Industrial Textile.
 - g. As regards the contention that the petitioner has not provided evidence to establish likelihood of injury, the Authority notes that petitioner claimed likelihood of injury on the basis of following parameters :
 - i. Chinese producers are looking towards export markets to make up for decline in domestic sales.
 - ii. India is the biggest export market for subject goods for Chinese exporters.
 - iii. Dumping margin in the previous investigations and present investigation is significant.
 - iv. Volume of imports since base period of original investigation.

- v. Freely disposable present and potential capacities with the foreign producers.
 - vi. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market.
 - vii. Price attractiveness of Indian market.
 - viii. Price undercutting in the absence of the measures.
 - ix. Even if one of the condition is satisfied, duty cannot be revoked.
- h. As regards the argument that likelihood of both dumping and injury should be established for extending the duties, it is clarified that the Authority has examined likelihood of both dumping and injury in the present case.
 - i. As regards the argument concerning decline in crude and petroleum product prices after the investigation period, it is reiterated that Authority first considers parameters prevailing during the POI to examine dumping and injury and/or likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Only in a situation where performance during the POI does not show dumping and injury and/or continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority considers the parameters for post POI.
 - j. As regards the argument that imports from China have declined in the POI, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the volume of import during present POI is sufficient enough to establish dumping and injury and/or likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
 - k. As regards the argument that the domestic industry's plants are more than two decades old, leading to higher cost, the Authority notes that the domestic industry on the other hand contended that their cost of production are unreasonably low and unrepresentative because of the fact that plants are fully depreciated and the domestic industry is having negligible interest cost. The domestic industry in fact has contended consideration of net present value of assets for determination of NIP.
 - l. As regards increase in import price in the present POI as compared to the base year, the Authority clarifies that the determination of continuation or likelihood of dumping and injury is based on the price prevailing during the POI.

G4. Economic Parameters of the Domestic Industry

- 39. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
- 40. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 41. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules supra.
- 42. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on the imports of the product under consideration, the Authority has considered whether improvement in performance of the domestic industry in respect of one or more parameters is due to the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from China PR. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
- 43. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

44. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd., constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows.

A. Volume Effect of dumped imports and impact on domestic Industry

(a) Demand and Market Share

45. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the country as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below. It is seen that demand of the product under consideration in the country has increased up to 2012-13 and then declined slightly in the POI. However, the demand has increased during the POI as compared to the base year. Sales of the domestic industry as well as imports of the subject goods from the subject country have increased in the POI as compared to the base year. It noted that market share of the domestic industry has not shown any significant improvement. However, the market share of imports from China has increased.

Demand and Market Share in India

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Demand in India					
Sales of Domestic industry	MT	62,995	64,879	66,745	66,505
Sales of Other Producers	MT	4,200	4,200	4,200	4,200
Imports from Subject Country	MT	23,120	28,631	31,909	29,461
Imports – Other countries	MT	44,529	38,344	40,821	40,038
Assessed Demand	MT	1,34,844	1,36,054	1,43,676	1,40,203
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	46.72	47.69	46.46	47.43
Other Indian Producers	%	3.11	3.09	2.92	3.00
Subject Country	%	17.15	21.04	22.21	21.01
Other Countries	%	33.02	28.18	28.41	28.56

*POI- Oct. '2012 – Sep. '2013

(b) Import volumes and market shares

46. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Volume of imports and imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
China PR	MT	23,120	28,631	31,909	29,461
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>138</i>	<i>127</i>
Other Countries	MT	44,529	38,344	40,821	40,038
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>92</i>	<i>90</i>
Total Imports	MT	67,649	66,975	72,730	69,498
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>108</i>	<i>103</i>
Subject Country Imports in relation to:					
• Total Imports	%	34.18%	42.75%	43.87%	42.39%
• Production	%	36.16%	44.01%	47.99%	44.11%
• Consumption	%	17.15%	21.04%	22.21%	21.01%

47. The Authority notes that imports of the subject goods from China PR have gradually increased in absolute terms from the base year up to 2012-13 and then declined in the POI as compared to the previous year. It is, however, noted that the imports from China PR in the POI were significantly higher than in the base year. Further, imports from the subject country have remained significant in relation to total imports, production and consumption in the POI. The share of imports from China in total imports increased over the injury period. The above situation prevails despite the existing anti dumping duty. The petitioner contended that the volume of imports from the subject country has remained high despite the existing anti dumping duty being in force and is, therefore, bound to increase in the absence of anti dumping duty.

B. Price Effect of the dumped imports and impact on the Domestic Industry

48. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of subject goods of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury. Thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

(a) Price Undercutting and Price Underselling

49. The price undercutting/underselling effects are examined below:

Price Undercutting

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Greige (Greige) Fabric					
Net Sales Realization	Rs/KG	***	***	***	***
Landed value of imports (without ADD)	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	***	***	***	***
Dipped Fabric		***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs/KG	***	***	***	***
Landed value of imports (without ADD)	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range %	15-25%	10-20%	10-20%	10-20%
Total					
Net Sales Realization	Rs/KG	***	***	***	***
Landed value of imports (without ADD)	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range %	15-25%	5-15%	10-20%	10-20%

50. The Authority notes that it is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The Authority notes that the imports from subject country would undercut the prices of the Domestic Industry in the Indian market in the absence of anti-dumping duty.

Price Underselling

Particulars	UOM	Greige	Dipped	Weighted Average
Import Volume	MT	15,855	13,606	29,461
Non-Injurious Price	Rs/KG	***	***	***
Landed Value	Rs/KG	***	***	***
Price Underselling	Rs/KG	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
Price Underselling	Range %	5-15%	5-15%	5-15%

51. The Authority notes that in the absence of anti dumping duty, the landed price of imports would be substantially below the non-injurious price of the domestic industry, thereby, resulting in significant price underselling effect.

(b) Price Suppression and Depression

52. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry and cost of sales has been compared with the landed price of imports. The data shows that the landed price of imports has remained below cost of sales and selling price of the domestic industry throughout the injury period, thus signifying significant depressing/suppressing effect on the prices of the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	115	115
Selling Price	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	113	113
Landed value of imports	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	119	120

C. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

53. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

54. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity (Greige and Dipped)	MT	96,929	1,08,797	1,16,938	1,17,500
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
Gross Production (Greige and Dipped)	MT	79,182	83,500	98,421	99,949
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>124</i>	<i>126</i>
Capacity Utilization(Greige and Dipped)	%	81.69%	76.75%	84.17%	85.06%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>103</i>	<i>104</i>
Gross Production of PUC(Greige and Dipped)	MT	77,839	80,024	95,087	98,130
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>122</i>	<i>126</i>
Net Production	MT	63,945	65,060	66,493	66,790
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>104</i>
Domestic Sales	MT	62,995	64,879	66,745	66,505
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
Demand	MT	1,34,844	1,36,054	1,43,676	1,40,203

55. The Authority notes that the domestic industry has enhanced its capacity for the production of the product concerned over the injury period. It is seen that the production and sales of the domestic industry increased over the injury period. However, there was decline in capacity utilization in 2011-12.

b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

56. The profits, return on investment and cash profit of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
Profit/loss	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>81</i>	<i>97</i>	<i>102</i>
Profit/loss	Rs. Lakh	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>83</i>	<i>103</i>	<i>107</i>
Profit before interest	Rs. Lakh	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>111</i>	<i>108</i>
Cash profit	Rs. Lakh	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>105</i>	<i>107</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>96</i>	<i>91</i>

57. The Authority notes from the above as under:

- The profitability of the domestic industry declined in 2011-12, increased in 2012-13 and again improved in the POI.
- The profits, profit before interest, cash profits and return on investment of the domestic industry showed the same trend as profitability. Return on investment of the domestic industry declined in the POI as compared to previous year 2012-13.
- It is noted that the profitability of the domestic industry has been stable over the period. The cash profits, profits before interest and return on capital employed have remained stable over the period. The petitioners have claimed that the stable performance of the Domestic Industry in respect of price parameters is reflective of the effects of anti dumping duty in force.

c) Market Share

58. The Authority notes that while the market share of the domestic industry has remained in similar region; the market share of imports from the subject country increased over the injury period. The petitioners have claimed that anti-dumping duty in force has prevented the producers in subject country to further capture the domestic market and hence the domestic industry is able to maintain its market share in demand. They have further claimed that should the anti-dumping duty cease, the subject country would once again capture the market share of the domestic industry, thereby, causing injury to the domestic industry.

d) Employment and Wages

59. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>120</i>

60. It is noted from the above that the employment level has increased up to 2012-13 and then marginally declined in the POI. Salary and wages increased over the injury period. The petitioners have contended that the increase in salary and wages show normal increase in wages.

e) Productivity

61. The productivity of the domestic industry is given in the following table.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Productivity Per Employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>108</i>	<i>206</i>	<i>226</i>
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>103</i>	<i>122</i>	<i>126</i>

62. The Authority notes that the productivity per employee and productivity per day have remained at the same level over the period as production.

f) Inventories

63. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the following table.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Stock (Volume) Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>121</i>	<i>89</i>
Inventory as number of Days Sales	Days	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>122</i>	<i>114</i>	<i>84</i>

64. It is noted from the above table that the inventory of the domestic industry increased up to 2011-12 and then declined. However, the inventory has remained significant in the POI.

g) Magnitude of Dumping

65. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined by the Authority against the subject country is above *de minimis* and significant.

h) Ability to raise capital

66. The Authority notes that the ability to raise capital investment in the event of dumping is not relevant since the constituents of the domestic industry are multi-product companies.

i) Growth

67. With regard to the growth of the domestic industry, the position is as under:

Growth percent (year by year)	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Production	%	-	5.45	17.87	1.55
Sales Volume	%	-	2.99	2.88	(0.36)
Cost of Sales	%	-	18.06	(2.76)	0.13
Selling Price	%	-	13.97	(0.95)	0.54
Profit per unit	%	-	(19.32)	20.50	4.48
Return on Investment	%	-	-3.86%	3.00%	-1.05%

68. The Authority notes that the performance of the domestic industry has shown positive growth in terms of both volume and price parameters. Domestic sales volumes, production, capacity utilization and market share; as well as profitability has shown improvement as can be seen from parameters such as profits, cash profits and return on investments. It is concluded that the growth of the domestic industry has not suffered materially as a result of the Chinese imports.

j) Factors Affecting Domestic Prices

69. The examination of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject country is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices from the subject country and other countries dumping the product. There is no viable substitute to this product. Demand for the product was showing significant increase and could not have been a factor responsible for price suppression faced by the domestic industry. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the import price of the product from the subject country.

k) Conclusion on injury

70. On the basis of various information on record and considering the legal provisions, the Authority concludes that the imports of the product under consideration from China have shown increase in absolute terms and its volumes have remained significant in relation to production and consumption in India. Share of Chinese imports have increased in relation to imports from various sources. The imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the market and the same is likely to lead to significant depressing or suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market in the event of cessation of anti dumping duty. Performance of the domestic industry has been stable or improved in respect of various economic parameters. Production and sales of the domestic industry has improved. Changes in the capacity utilization, profits, return on investments and cash flows are marginal and show stable condition of the domestic industry. Even though the ROI earned by the domestic industry is below the 22% levels considered by the Authority, the domestic industry is earning positive return on investment. It is thus concluded that the domestic industry has not suffered continued injury as a result of continued dumping.

D. Other Known Factors and Causal Link

71. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(a) Volume and Prices of imports not sold at dumped prices

72. The Authority notes that the domestic industry is facing injury from dumped imports entering into the country from China PR. Imports of product under consideration from other countries are either *de minimis* or the export prices are high.

(b) Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

73. The Authority notes that demand for the product has grown over the injury period, except a slight decline in the POI. However, demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to the base year. Hence, possible decline in demand cannot be a factor causing injury to the domestic industry. Further, the Authority has found no evidence of a change in the pattern of consumption of the product.

(c) Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

74. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

75. The Authority notes that there are no developments in technology with respect to the product or its manufacture that could have resulted in the injury caused to the domestic industry.

(e) Export performance

76. The Authority notes that the domestic industry has exported the product in small quantity over the injury period. The negligible exports, therefore, show that the injury claimed by the domestic industry is in respect of domestic sales only.

(f) Productivity of the domestic industry

77. The Authority notes that productivity of the domestic industry has moved in accordance with the production. Hence, a decline in productivity cannot be a cause for the injury determined.

(g) Performance of other products

78. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury found since all parameters were examined with respect to the like article in this investigation.

79. The Authority notes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined; the following parameters show that injury to the domestic industry is likely from dumped imports in the event of cessation of anti dumping duty.

- a. Imports from the subject country have continued to enter India at dumped prices.
- b. The margin of dumping, price undercutting and injury margin are quite significant.
- c. Imports would undercut the prices of the domestic industry in the absence of anti dumping duty. Further, the landed price of imports without anti dumping duty is below not only selling price of the domestic industry but also cost of production and non injurious price of the domestic industry.
- d. Despite the existence of anti-dumping duties in force on imports from China, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

(E). Conclusion on Injury and Causation

80. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India has been significant despite the fact that anti dumping duty is in force. Production and sales of the domestic industry have increased. Profit-related parameters have also shown improvement. The Authority notes that the domestic industry has not suffered continued injury in the POI. However, the Authority also notes that even if the domestic industry is not suffering injury in the POI in terms of profits, the volume of Chinese imports in the POI is significant enough to cause injury to the domestic industry should the domestic industry be forced to match the prices with the landed price of imports of the subject goods from China as the same is significantly lower than the non-injurious price of the domestic industry. However, imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Dumping margin, price undercutting and injury margin are significantly positive. However, despite significant dumping margin, this review being a sunset review, the Authority has examined the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the POI in the event of revocation of anti dumping duties.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1 Submissions by the exporters/opposing interested parties

81. The exporters/opposing interested parties have made the following submissions with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury:-

- i. The first proviso to Section 9A (5) lays down that the extension of duties is dependent on the likelihood of continuation or recurrence of both dumping and injury. The likelihood of injury or dumping in isolation cannot make the case for further extension of duties.
- ii. The information on production capacities of the Chinese producers does not provide details on their commitment to supply the subject goods to India.

H.2 Submissions by Domestic Industry

82. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury:-

- i. There is continued dumping of the product under consideration from China. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from China should the current anti-dumping duty be revoked.
- ii. The landed price of imports from China is lower than the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. These producers would, therefore, aggressively target Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.
- iii. Exporters in the subject country have capacities far in excess of Indian demand.
- iv. It is apparent from the Annual Report of Junma Tyre Cord Company Limited, which is the largest producer of Nylon 6 tyre cord in the PRC, that the company was able to increase their sales despite so many adverse factors because they were selling to export markets at prices below normal value to drive sales and make up for the domestic losses. This strategy is being adopted by other exporters of the subject goods also in the subject country. Chinese producers are looking towards export markets to make up for decline in the domestic sales.
- v. Considering the known capacity available with some of the producers in China to the level of 3.69 lac TPA and the Indian demand of approximately 1.4 lac TPA, there is strong likelihood that dumping is likely to intensify in the event of revocation of anti-dumping duties.
- vi. An analysis of the data on China's exports to the world makes it apparent that India is one of their biggest export markets for the subject goods.
- vii. India is a lucrative market for the subject goods as the export prices from China to India have been consistently below export prices to other countries.
- viii. In the current period of investigation, the volume of dumped imports has remained significant, and the dumping margin is also quite significant. This clearly establishes that the dumping is likely to continue and indeed intensify in the event of revocation of present anti-dumping duty. Significant current dumping margin in the presence of anti-dumping duty is a strong indication of likelihood of dumping.
- ix. Dumped imports from the subject country have remained significant and continue to hold significant market share. Further, the landed price from China would significantly undercut the Indian prices in the absence of anti dumping measures. Thus, cessation of anti-dumping duty shall cause significant price suppressing and depressing effect.
- x. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of low priced imports from the subject country in the market would cause an adverse impact on the Domestic Industry.
- xi. In the event of cessation of current anti-dumping duty and if domestic industry chooses to sell at import prices, the domestic industry would suffer significant financial losses.

H.3 Examination by the Authority

83. The present investigation is second sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of Nylon Tyre Cord Fabric from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this case, as there are continued dumped imports, the Authority is required to examine whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to continued dumping of the product. Exporters and producers from the subject country are exporting the subject goods at dumped prices. In the previous investigations also dumping margin was significant. In such a situation, the Authority has no reason to believe that dumping will not intensify if the anti dumping duty ceases. Further, considering the fact that the dumping margin in the previous as well as the present investigation is significant and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reasons to believe that dumping may intensify if the duty ceases. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country is

continuing dumping of the subject goods in the Indian market. The following analysis shows about the likelihood of intensified dumping and further injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties.

Level of current and past dumping margin

84. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigation and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports continue to be made at dumped prices and are likely to continue with the cessation of anti dumping duties. The volume of imports from the subject country has remained significant throughout the injury period. Further, the volume of imports is likely to increase further in the event of cessation of anti-dumping duties.

Price attractiveness of Indian market

85. The prices at which the subject goods are being imported are materially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding huge capacities. Further, as claimed by the domestic industry, such circumstances would result in likelihood of injury to the domestic industry.

Significant capacities with the subject country

86. The evidence provided on the existing capacity in China by DI indicates that it is far greater than the Indian demand for the subject goods. In the event of revocation of anti-dumping duty, the producers in China are likely to intensify dumping of the subject goods.

Export orientation of foreign producers

87. From the available information it is noted that the Chinese producers/exporters are very much export oriented. Considering the high demand and favourable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of the Chinese producers, the Authority holds that if the existing anti dumping duty is withdrawn, there is likelihood of substantial demand for the subject goods in India to be catered by the Chinese producers/exporters.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

88. Considering the current level of imports from the subject country in spite of existing anti dumping duty, there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices would undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

Magnitude of injury and injury margin

89. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin based on monthly analysis so worked out is as under:

Injury Margin

Particulars	M/s Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	Non-Cooperative exporters
Wt. Avg. NIP of DI	***	***
Landed Value	***	***
Injury Margin	***	***
Injury Margin %	***	***
Injury Margin Range%	10-20	25-35

90. It is noted that the level of injury margin, as determined, is considered significant.

I. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

(A) Post Disclosure comments of the opposing interested parties

- Jumna Tyre Cord Company Ltd, China
- Ningbo Nylon Company Ltd, China
- Huaian Nylon Chemical Fibre Company Ltd, China
- Ningbo Jinlun Import and Export Company Ltd, China

➤ Automotive Tyre Manufacturers' Association

91. The Authority notes that post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. The opposite interested parties have, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:
- (i) Merely three days time provided to comment on the Disclosure Statement cannot be construed as sufficient.
 - (ii) Detailed questionnaires' response filed by the above mentioned exporters has not been taken on record despite their filing request to the Authority seeking time extension to file the response, which was not rejected.
 - (iii) The domestic industry always tends to match its selling prices with the landed value of the subject goods; and since the landed value would include the ADD in force; axiomatically, the selling price would be somewhat at a similar level. Thus, without the anti-dumping duty in force, there would always be a case of price undercutting.
 - (iv) The Authority has squarely failed to consider the fact that bulk of these imports has been effected under the duty free schemes of the Foreign Trade Policy wherein the anti-dumping duty remains inconsequential.
 - (v) In an SSR matter, the Authority is obliged to ascertain the likelihood of any continuation or recurrence of dumping and injury in the event of expiration of the antidumping duty. Therefore, the data that should have been analyzed as close as possible to the date of expiry of the duty in force.
 - (vi) The determination of dumping margin is based on a flawed assumption of normal value, as the above mentioned exporters had claimed MET status and an examination thereof would have found that the normal value in their case is significantly lower.
 - (vii) Excessive and unwarranted confidentiality has been claimed by the applicants.
 - (viii) The domestic industry did not have sufficient dipping facility of NTCF and hence, the user industry had little choice but to import the said goods from the overseas sources.
 - (ix) There is no likelihood of dumping and injury as there has been a decrease in the imports of the subject goods from China during the POI and Chinese exporters have not been India-Centric. This signifies that Chinese exporters have moved their focus to supplying to other markets. It is apparent that the Chinese capacity additions are committed towards third country markets rather than Indian markets.
 - (x) The Authority has accepted that the domestic industry has not suffered continued injury. Therefore, it is an established fact that the domestic industry is not currently suffering any injury.
 - (xi) The Authority's conclusion that the lack of current injury and the significant improvement in the domestic industry's performance is due to the existence of anti-dumping duty lacks basis.
 - (xii) The domestic industry is not facing continued injury. There is increase in price and decrease in volume of Chinese imports, increase in market share of the domestic industry, increase in domestic industry's production, capacity and capacity utilization, improvement in productivity of domestic industry, increase in profits, return on investment and cash flow etc.
 - (xiii) There is lack of evidence to show likelihood of recurrence of injurious dumping.
 - (xiv) Focus of the domestic industry on exports could be responsible for stagnant market share in domestic sales.
 - (xv) Comparisons have been made with preceding period or base year to suit the domestic industry's interest.
 - (xvi) There has been a significant fall in the prices of Crude & Petroleum products from US\$ 130 to US\$ 40. The POI adopted should not be considered as barometer for levying anti dumping duty, or the anti dumping duty must be levied on ad valorem basis to account for the fluctuations in the prices of the subject goods from time to time.

(B) Post Disclosure Comments of the Domestic Industry

92. The Authority notes that most of the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. Following are, in brief, the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:
- (i) The Authority has rightly proposed to treat all exporters in China as operating under non-market economy conditions.
 - (ii) Normal value has been determined considering constructed cost of production, whereas the domestic industry provided sufficient information with regard to cost or price in market economy third country (Thailand). Petitioners reiterate that the normal value cannot be determined on the basis of "any other information" when information on cost and price in market economy third country is available.
 - (iii) The investigation has established existence of significant dumping.
 - (iv) There have been significant imports of the product from the subject country in absolute terms, thus establishing likelihood of dumping in case of cessation of anti dumping duty.

- (v) Performance of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has improved in the current injury period. However, cessation of anti dumping duty shall have significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market, given significant price undercutting in the event of cessation of anti dumping duty.
- (vi) Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
- (vii) The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The domestic industry would, therefore, be forced to either reduce the prices or loose sales opportunities. In either situation, the domestic industry is likely to suffer injury.
- (viii) The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti dumping duty.
- (ix) The non injurious price should be determined considering the present value of the assets.
- (x) The anti dumping duty is required to be continued. Duty may be recommended on fixed amount basis in US\$ term.

(C) Examination by the Authority

93. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

- (i) As regards the contention that the time available for offering comments to Disclosure Statement was insufficient, the Authority notes that the opposite interested parties have not only filed elaborate comments but also these are repetitive. Further, there is no prescribed minimum time under the Rules for offering comments to the Disclosure Statement.
- (ii) The above mentioned exporters by their own admittance filed questionnaires' response after the prescribed time limit. Therefore, the same were not on the record of the Authority. Thus, the question of not issuing any rejection letter by the Authority does not arise.
- (iii) As regards the contention that without the anti-dumping duty in force, there would always be a case of price undercutting, it is noted that the prices at which the subject goods are being imported are significantly lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market.
- (iv) As regards the contention that the imports of the product are under duty free scheme category and, therefore, the volume of imports is irrelevant to determine likelihood, the Authority notes that the price at which duty free imports have been made during the POI and the volume of imports during the POI clearly show the price at which the goods are likely to be imported in the event of cessation of anti dumping duty. It is also noted that the Authority has been consistently considering the fact that the imports made under duty free category does not imply that the same do not cause injury to the domestic industry.
- (v) As regards the submissions concerning the period that should be considered for determination, the Authority notes that the POI considered in the present case is appropriate. There is no statutory requirement that the POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty. Further, post POI period of 6 months has been adopted by the Authority in the past also in numerous sunset review investigations.
- (vi) As regards the submissions that the determination of dumping margin is based on a flawed assumption of Normal value, as the above mentioned exporters had claimed MET status, the Authority notes that their Exporters Questionnaires have been rejected because of late filing.
- (vii) As regards the argument on confidentiality of information in the petition, it is noted that the Authority has granted confidentiality wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.
- (viii) As regards the contention that the domestic industry did not have sufficient dipping facility of NTCF, the Authority notes that as per the evidence on record the domestic industry has sufficient dipping facility but is not in a position to match the prices of the dipped NTCF with the dumped prices of dipped NTCF from the subject country.
- (ix) As regards the contention that there is no likelihood of dumping and injury, it is noted that there is already evidence of significant dumping and injury in the period of investigation itself which dilutes the need for examining the likelihood analysis of dumping and injury. The prices at which the subject goods are being imported are materially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding huge capacities. The evidence provided on the existing capacity in China by DI indicates that it is far greater than the Indian demand for the subject goods. In the event of revocation of anti-dumping duty, the producers in China are likely to intensify

dumping of the subject goods. From the available information it is noted that the Chinese producers/exporters are very much export oriented. Considering the high demand and favourable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of the Chinese producers, the Authority holds that if the existing anti dumping duty is withdrawn, there is likelihood of substantial demand for the subject goods in India to be catered by the Chinese producers/exporters. It is further noted that the import prices would undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

- (x) As regards the contention that it is an established fact that the domestic industry is not currently suffering any injury, the Authority notes that the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India has been significant despite the fact that anti dumping duty is in force. Even if the domestic industry has not suffered continued injury in the POI, the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and further, dumping margin and injury margin are significantly positive.
- (xi) As far as the claim of the domestic industry to consider Thailand as the appropriate country to determine the Normal Value for China, the Authority is of the view that the applicant domestic industry has not provided sufficient reasons/information for the selection of Thailand as the appropriate market economy country for China, the subject country. The Authority is of the view that considering the much higher level of overall economic development in China and production cost, capacity and export orientation in China with respect to the product concerned, it would not be appropriate to consider China and Thailand as comparable.
- (xii) As far as the issue of non-injurious price is concerned, the Authority has determined the non-injurious price as per the guidelines laid down in Annexure III to the AD Rules.
- (xiii) As far as the issue of recommending the duty in fixed amount in US\$ terms is concerned, the Authority noted that the form of duty is decided by the Authority keeping in view the nature, circumstances and merits of the individual case and accordingly, the form of duty and the currency of the duty has been determined in this case.
- (xiv) It is noted that the domestic industry is largely operating in the domestic market and export sales as a percentage of total sales of the domestic industry is negligible.
- (xv) The Authority has followed the past practice of analysis and examination consistently. All parameters of injury have been examined with reference to the complete investigation period.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

- 94. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply.
- 95. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the product to the consumers.

K. CONCLUSION

- 96. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
 - a. There is continued dumping of the subject goods from the subject country and the dumping margin is above de-minimis and significant. Dumped imports are causing injury to the domestic industry in the period of investigation.
 - b. Should the present anti-dumping duties cease, dumping of the subject goods from the subject country is likely to get intensified causing consequent injury to the domestic industry.

L. RECOMMENDATIONS

- 97. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be

recommended to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and its consequential injury to the domestic industry.

98. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, by the Central Government.

Duty Table

S. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Grade	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	China PR	China PR	Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	0.52	Kg	US\$
2.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	China PR	China PR	Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	Any other	1.10	Kg	US\$
3.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	China PR	China PR	Any other	Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co. Ltd.	1.10	Kg	US\$
4.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	China PR	China PR	Any other than the S. No 1,2 and 3 above		1.10	Kg	US\$
5.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.10	Kg	US\$
6.	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	All Grades	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	1.10	Kg	US\$

M. FURTHER PROCEDURE

99. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
100. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority